कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक
प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल

कला संपादक
धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क
वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क
InL;rk : +91(11) 23005798
Qksu (dk-) : +91(11) 23381428
QSD : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

सरकार की उपलब्धियां

राष्ट्रपति अभिभाषण.......... 7
एयरो इंडिया 2015.......... 8
स्वस्थ धरा, खेत हरा.......... 20
कोयला ब्लॉकों की नीलामी.......... 27

संगठनात्मक गतिविधियां

सदस्यता महाभियान

साक्षात्कार : दिनेश शर्मा.......... 10
: अरुण सिंह.......... 12

श्रद्धांजलि

वरिष्ठ भाजपा नेता हरीशचंद्र श्रीवास्तव नहीं रहे.......... 13

वैचारिकी : पं. दीनदयाल उपाध्याय

'सब को काम' ही भारतीय अर्थनीति का एकमेव मूलाधार.......... 14

अन्य

अरुणाचल प्रदेश.......... 19
मन की बात.......... 21
श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला से मिले मोदी.......... 22
ईसाई धर्म गुरु सम्मेलन.......... 24
झारखण्ड.......... 25
असम : स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की भारी जीत.......... 29
अनूठी पहल.......... 30

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

शिवाजी का अभिमान

छत्रपति शिवाजी ने अपने पराक्रम से अनेक युद्धों में विजय पाई। इससे उनके मन में थोड़ा अभिमान आ गया। उन्हें लगता था कि उनके जैसा वीर धरती पर और कोई नहीं है। कई बार तो उनका यह घमंड औरों के सामने भी झलक पड़ता। एक दिन शिवाजी के महल में उनके गुरु समर्थ रामदास पधारे। शिवाजी वैसे तो अपने गुरु का बहुत आदर करते थे, लेकिन उनके सामने भी उनका अभिमान व्यक्त हो ही गया। उन्होंन कहा, 'गुरुजी अब मैं लाखों लोगों का रक्षक और पालक हूं। मुझे उनके सुख-दुख और भोजन-वस्त्र आदि की हर समय चिंता करनी पड़ती है।'

रामदास समझ गए कि उनके शिष्य के मन में राजा होने का अहंकार हो गया है। इसे तोड़ने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। शाम को शिवाजी के साथ भ्रमण करते हुए रामदास ने अचानक उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाते हुए कहा, 'शिवा, जरा इस पत्थर को तोड़कर तो देखो।' शिवाजी ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए तत्काल वह पत्थर तोड़ डाला। किंतु यह क्या, पत्थर के बीच से एक जीवित चींटी एक दाना मुंह में दबाए बैठी दिखी।

यह देखकर शिवाजी चकित रह गए। फिर समर्थ रामदास ने पूछा, 'पत्थर के बीच बैठी इस चींटी को कौन हवा-पानी दे रहा है? इसका पालक कौन है? कहीं इसके पालन की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर तो नहीं आ पड़ी है शिवा?' शिवाजी गुरु की बात का मर्म समझकर लज्जित हो गए। गुरु ने उन्हें समझाया, 'पालक तो सबका परम पिता परमेश्वर है। हम-तुम तो माध्यम भर हैं। उस पर विश्वास रखकर कार्य करो। सफलता अवश्य मिलेगी।' शिवाजी गुरु का संकेत तुरंत समझ गए।

संकलन : आर.डी. अग्रवाल 'प्रेमी' (नवभारत टाइम्स)

पाथेय

प्रत्येक देशभक्त व्यक्ति की ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक ही है कि अपना देश वैभवशाली बने। राष्ट्र सुखी, संपन्न बने। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़े। बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशांति का अंत हो। न्याय सुलभ हो। आपसी झगड़े समाप्त हों। सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, भाषायी संकुचितताओं से ऊपर उठकर लोगों के सोचने, विचारने का तरीका हो। दलीय अभिनिवेशों से नेतागण मुक्त हों। भारत अपने राष्ट्रीय स्वरूप में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक सभी प्रकार के क्षेत्रों में लोककल्याणकारी सिद्ध हो। जिसमें ऐसी इच्छा निर्माण नहीं होती हो, उसे भारतीय तो क्या मानव कहना भी कठिन है। स्व. मैथिलीशरण गुप्त जी के शब्दों में कहना हो तो ''जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नरपशु निरा है और मृतक समान है।'' अपने देश को गौरवशाली देखने की इच्छा प्रत्येक जीवंत भारतीय के हृदय में उठना स्वाभाविक है।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय ('राष्ट्र जीवन की दिशा')

नीतीशजी, जनता मूर्ख नहीं है!

ढाई दशक से बिहार की राजनीतिक जीवन-यात्रा अस्थिर रही है। इस ढाई दशक में सात वर्ष भाजपा-जनता दल (यू) गठबंधन की सरकार ने जनविश्वास से जनादेश प्राप्त कर बिहार की राजनीति और विकास को पटरी पर लाने का अथक प्रयास किया। इस प्रयास की सच्चाई यह थी कि भाजपा कार्यकर्ताओं, जो बिहार के गांव-गांव और चप्पे-चप्पे में है, ने श्री नीतीश कुमार को सच में गठबंधन का नेता मान लिया था। यही कारण रहा कि बिहार में एक बार नहीं दो-दो बार भाजपा-जदयू गठबंधन को तीन-चौथाई से अधिक समर्थन मिला।

लेकिन जब आदमी बुलंदियों पर होता है तो वह सच में भूल जाता है कि उसकी बुलंदी का आधार क्या है? और धीरे-धीरे आधार को भूलने के बाद उसमें अहंकार जन्म लेता है। यही अहंकार नीतीश कुमार को ले डूबा। लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं के कंधों पर सवार नीतीश कुमार को लगा कि भाजपा शायद उनके कारण बिहार में है। वे सच्चाई को भूल गये कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें बाबा वैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवर-यात्रियों की तरह अपने कंधों पर ढोकर विजयश्री प्राप्त करवाई।

नीतीश कुमार का अहम उस समय चरमोत्कर्ष पर आ गया जब वे सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में भाजपा और नरेन्द्र मोदी की बुराई कर प्रधानमंत्री पद की ओर बढ़ने के लिए लालायित हो गये। और उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने भाजपा-जदयू गठबंधन को पैरों तले कुचल दिया।

वे शायद यह नहीं जानते थे कि भाजपा एक विचार एवं परिवार है और नीतिश कुमार एक अकेला व्यक्ति! ढोल की पोल पिछले लोकसभा चुनाव में खुल गई। गठबंधन तोड़ने का दंड ईश्वर ने (जनता-जनार्दन) ने ऐसा दिया कि नीतीश कुमारजी चारों खाने चित्त हो गये। स्थिति इतनी भयावह बनी कि वे मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बन चुके नरेन्द्र मोदी से कैसे आंखें मिलाते? शर्मसार आंखों की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। वे इस बात को छुपाकर पुनः एक राजनीतिक चाल चले और अपने को नैतिकता का शेरपा तेनसिंह साबित करने में लग गये। नैतिकता की आड़ ली और महादलित जीतन राम मांझी को यह सोचकर कि यह तो मेरी कठपुतली और खड़ाऊं मुख्यमंत्री रहेगा, खुद इस्तीफा देकर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। नैतिकता की दुहाई देने वाले नीतीश कुमार की पोल उस समय और अधिक खुल गई जब वे बतौर पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में मुख्यमंत्री की हैसियत से बढ़-चढ़कर घूमने लगे। बिहार के लोग यह कहने लगे कि सुपर मुख्यमंत्री तो नीतिश कुमार है।

धीरे-धीरे समय बीतता गया, महादलित जीतन राम मांझी उनकी पकड़ से बाहर होने लगे। इतना ही नहीं, बिना पूछे बयान देने लगे और कैबिनेट के फैसले लेने लगे। सुपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह सब बातें नागवार गुजरीं और उन्होंने जीतन राम मांझी को अपने समर्थकों द्वारा पागल बताया और ऊल-जुलुल बयान देने वाले व्यक्ति के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। बात यहीं नहीं थमी, नीतीश कुमार ने अपने समर्थकों द्वारा महादलित मांझी को हटाने की मांग भी करवाने लगे। इस बीच में, मांझी ने बतौर मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गाहे-बगाहे प्रशंसा शुरू कर दी। फिर क्या था, करेला और वह भी नीम चढ़ा। नीतीश कुमार को लगा जिस मांझी को हमने लोकतांत्रिक बुद्धू समझा था वह तो सच में एक राजनैतिक नेता के रूप में उभरने लगा है। फिर नीतिश कुमार ने जदयू में मांझी के खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ दी।

जदयू की स्थिति बद से बदतर तो तब हो गई जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने विधान मंडल दल की बैठक बुलाई और मांझी ने कहा कि यह संवैधानिक रूप से गलत है। मांझी को इस

बात का अंदेशा लग गया था कि आठ माह पूर्व नीतीश कुमार के मन में पैदा हुई नैतिकता, अब नारकीयता में बदल गई है और वे पुनः मुख्यमंत्री बनने जैसे इच्छाधारी सांप का रूप लेने लगे हैं। यह कारण था कि मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार का महादलित प्रेम कहां गया? उन्होंने नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी "मुझे बताओ मेरी गलती क्या है?" शरद यादव से लेकर नीतीश कुमार तक इस बात में प्रण-पण से जुट गये कि मांझी हटे - नीतीश बने।

जब भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी के बयानों की भर्त्सना करती थी तब जदयू के लोग यह कहा करते थे कि भाजपा महादलित विरोधी है, जबकि सच्चाई यह है कि यह तो जदयू की आंतरिक लड़ाई थी। जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था तब उन्होंने भाजपा से पूछकर जीतन राम मांझी को न मुख्यमंत्री बनाया था न कोई बात की थी। भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं था। पर नीतीश कुमार एवं जदयू ने जिस तरह से जीतन राम मांझी को अपमानित कर हटाने की प्रक्रिया शुरू की उसका भाजपा ने विरोध किया।

भाजपा का कहना साफ था कि नीतिश कुमार अपनी महत्वाकांक्षा के आगे महादलित मांझी की राजनीतिक हत्या कर उन्हें अपमानित कर रहे है। यह बात सच निकली। जीतन राम मांझी ने स्वयं कहा कि मैंने कोई काम बिना नीतीश कुमार से पूछे नहीं किया। नीतीश कुमार को जदयू के अस्तित्व की नहीं वरन् अपने राजनैतिक भविष्य एवं महत्वाकांक्षा की अहम चिंता हो गई थी। और यही कारण है कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पहले भाजपा से गठबंधन तोड़ने का निर्णय लिया और दूसरा महादलित जीतन राम मांझी को बतौर मुख्यमंत्री अपमानित कर हटाने का निर्णय लिया। बिहार की जनता नीतिश कुमार को माफ नहीं करेगी।

समाजवादी राजनीतिक इतिहास में आचार्य नरेन्द्र देव, डॉ. राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इन तीनों नेताओं ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि समाजवाद की आड़ में नीतीश कुमार व्यक्तिवाद की धारा बहा देंगे।

समाजवादी विचार के इस गिरते स्तर पर उन सभी समाजवादियों को मंथन करनी चाहिए, जिन्हें समाजवाद की थोड़ी भी चिंता है। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को कोस-कोस कर उनके माफिया और जंगल राज के साथ-साथ चारा घोटाले में आरोपी बनाने में जिस नीतीश कुमार ने गांव-गांव में अलख जगाया, आज अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए ऐसे अनेक आरोपों से जड़ित लालू यादव के चरणों में गिरकर किस नैतिकता का परिचय दे रहे हैं?

पद-लिप्सा की हद तो तब हो गई जब अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार न केवल 'लालू शरणम् गच्छामी' हुए बल्कि 'सोनिया शरणम् गच्छामी' भी हो गये। जिस लालू-सोनिया के खिलाफ बिहार की जनता ने भाजपा-जदयू गठबंधन को समर्थन दिया, उसी लालू और सोनिया को साथ लेकर नीतीशजी समझते हैं कि जनता का समर्थन प्राप्त कर लेंगे। नीतीश जी, जनता मूर्ख नहीं है!

पिछले कुछ वर्षों में जो बिहार का विकास अवरूद्ध हुआ है और बिहार की राजनीति को ग्रहण लगा है, उसके एकमात्र जिम्मेदार नीतीश कुमार ठहराये जा रहे हैं। बिहार की जनता देश के अन्य राज्यों की तुलना में ना केवल राजनीतिक रूप से समझदार बल्कि लोकतांत्रिक रूप से परिपक्व भी हैं। जनता उचित समय का इंतजार कर रही है और समय आने पर जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य पर जनता के समर्थन में जुट जाना चाहिए। समय आपातकाल का रहा हो या पूर्व के किसी क्रांति का, उन सभी के लोकतांत्रिक विरोध का सबसे बड़ा केन्द्र बिहार रहा है। बिहार राजनीतिक स्थिरता चाहता है, बिहार एक सुयोग्य नेतृत्व चाहता है, बिहार राज्य को प्रगति पथ पर ले जाने वाले एक अहम राजनीतिक दल की तलाश कर रहा है। बिहार नरेन्द्र मोदी की विकास गाथा के साथ जुड़ना चाहता है। इसलिए भाजपा के राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व को सोच-समझकर, परिश्रम से जनता की मनोभावना समझते हुए उनके दिल को जीतन में प्राण-पण से जुटना होगा।

■

'भूमि अधिग्रहण कानून में इससे प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी'

गत 23 फरवरी को राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं।

उनके बजट अभिभाषण में कही गयी दस प्रमुख बातें-

1. राष्ट्रपति ने संसद सत्र आपसी सद्भावना से चलाने का सांसदों से किया अनुरोध

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने सभी सांसदों से अनुरोध किया कि वे सहयोग और आपसी सद्भावना के साथ अपने उत्तरादायित्वों का निर्वहन करें।

2. सरकार काले धन से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए प्रतिबद्ध

सरकार विधायी और प्रशासनिक ढांचों के जरिए काले धन का सृजन रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि 'अधिकतम सुशासन और न्यूनतम सरकार' का सिद्धांत सरकार की गतिवधियों को दिशानिर्देश प्रदान करेगा।

3. भूमि अधिग्रहण कानून में उपयुक्त सुधार किये गए हैं

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें उपयुक्त सुधार किये गए हैं ताकि आधारभूत ढांचे की महत्वपूर्ण जनपरियोजनाओं में प्रक्रियागत समस्याओं को कम करने के साथ ही किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

4. बेटियों के जन्म पर खुश हों लोग, लाना होगा ऐसा बदलाव

शिशु लिंग अनुपात में निरंतर कमी को अत्यंत चिंता का विषय बताते हुए राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' अभियान की शुरुआत की है जो लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए है ताकि वे बेटियों के जन्म पर भी हर्षित हों।

उन्होंने कहा, '' सन 1961 से ही शिशु लिंग अनुपात में निरंतर कमी होना अत्यंत चिंता का विषय है. इस चलन को बदलना होगा। बेटियों के जीवन, सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' अभियान की शुरुआत की है जो लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए है ताकि वे बेटियों के जन्म पर भी हर्षित हों।

5. निर्णायक पहलों के कारण मुद्रास्फीति रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार के कई निर्णायक कदमों के कारण मुद्रास्फीति रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और अर्थव्यवस्था फिर से उच्च वृद्धि के मार्ग पर है।

उन्होंने कहा ''सरकार द्वारा उठाए गए कई निर्णायक कदमों के कारण मुद्रास्फीति और विशेष तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर है।'' थोक मुद्रास्फीति पिछले तीन महीने में दूसरी बार शून्य से नीचे चली गई और पेट्रोलियम और खाद्य मूल्य में गिरावट के कारण यह जनवरी में शून्य से 0.39 प्रतिशत कम के साढे पांच साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई।

6. जनधन योजना के तहत 13.2 करोड़ नये खाते खोले गये

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पिछले छह महीने में 13.2 करोड़ नये बैंक खाते खोले गये और जमा के रुप में 11,000 करोड रुपये से अधिक प्राप्त हुए। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए श्री मुखर्जी ने कहा कि महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

7. अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडे और गरीब का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा

शेष पृष्ठ 9 पर

घरेलू रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करने की पहल का वादा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा उद्योग के लिहाज से भारत के एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के तौर पर उभरने का भरोसा जाहिर करने के साथ ही वादा किया कि घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए पक्षपातरहित कर प्रणाली समेत अनुकूल कारोबारी माहौल प्रदान किया जाएगा। गत 18 फरवरी को एयरो इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुपरिचित रक्षा चुनौतियों के मद्देनजर देश को अपनी रक्षा तैयारी बढाने और अपनी सेना के आधुनिकीकरण की जरुरत है।

साथ ही उन्होंने विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि वे सिर्फ विक्रेता बनने के बजाय रणनीतिक भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान आयात को कम करने और मिशन की भावना के साथ घरेलू रक्षा उद्योग को विकसित करने पर है। उन्होंने कहा कि मिशन की यह भावना 'मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मूल है।' उन्होंने कहा 'हम ऐसा उद्योग विकसित करेंगे जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों सहित हर किसी के लिए जगह होगी।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा गतिशील रक्षा उद्योग विकसित करने की है। साथ ही उन्होंने अनुकूल कारोबारी माहौल के प्रति आश्वस्त किया। श्री मोदी ने कहा कि मजबूत रक्षा उद्योग न सिर्फ देश को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा बल्कि इसे और संपन्न भी बनाएगा।

बेंगलुरु के बाहरी क्षेत्र में स्थित भारतीय वायु सेना के येलाहांका एयर बेस पर एशिया के प्रमुख एयर शो में प्रधानमंत्री ने कहा 'हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी कर प्रणाली के तहत आयात के मुकाबले घरेलू विनिर्माताओं के साथ पक्षपात न हो।' श्री मोदी ने कहा, 'यदि हम देश में विनिर्माण क्षेत्र का बदलाव कर सके तो भारत का रक्षा क्षेत्र और सफल होगा।'

आयात घटाने की जरुरत पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा 'यदि हम अगले पांच साल में घरेलू खरीद का अनुपात बढ़ाकर 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत कर सकें तो हम अपने रक्षा क्षेत्र का उत्पादन दोगुना कर सकेंगे।' उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दिनों आए अध्ययन से स्पष्ट है कि आयात में 20-25 प्रतिशत तक की भी कमी हो तो इससे सीधे तौर पर देश में बेहद कुशल लोगों के लिए एक लाख से 1,20,000 तक अतिरिक्त रोजगार सृजन किया जा सकेगा।

श्री मोदी ने देश की अनुसंधान एवं विकास प्रक्रिया में वैज्ञानिकों, सैनिकों, शैक्षणिक समुदाय, उद्योग और स्वतंत्र विशेषज्ञों को और मजबूती से जोड़ने की भी बात कही। श्री मोदी ने कहा कि एक अरब आबादी वाले देश के तौर पर भारत में आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की भी भारी जरुरत है। उन्होंने कहा, 'हम प्रौद्योगिकी और प्रणाली को इससे जोड़ रहे हैं।'

प्रधानमंत्री ने एयर शो में भागीदारी कर रहे विदेशी शिष्टमंडलों से कहा कि उनमें से बहुतों के लिए भारत प्रमुख कारोबारी अवसर है जो रक्षा उपकरणों के लिए सबसे बडे वैश्विक आयातक के तौर पर मशहूर है। श्री मोदी ने इस द्वैवार्षिक समारोह के मौके पर कहा 'आपमें से बहुतों को यह सुनने में अच्छा लगता होगा लेकिन यह ऐसा क्षेत्र है

जिसमें हम अव्वल नहीं रहना चाहते।'

इस मौके पर 250 से अधिक भारतीय और 300 विदेशी कंपनियों हिस्सा लिया। अब तक के सबसे बडे एयरो इंडिया शो में विश्व भर के रक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सैंकड़ों उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया जिसमें मोदी का 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम केंद्र में रहा। उन्होंने कहा 'हमारी सुरक्षा चुनौतियां सुपरिचित हैं तथा हमारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां स्पष्ट हैं और हमें भी अपनी रक्षा तैयारी बढाने की जरुरत है। हमें अपने रक्षा बलों के आधुनिकीकरण की भी जरुरत है। हमें अपने आपको भविष्य की जरुरत के लिए तैयार करना है जिसमें प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका होगी।'

उन्होंने कहा कि मजबूत रक्षा उद्योग न सिर्फ भारत को और सुरक्षित बनाएगा बल्कि संपन्न भी बनाएगा। श्री मोदी ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि भारत रक्षा उद्योग के लिए प्रमुख वैश्विक केंद्र बनकर उभरेगा।' श्री मोदी ने कहा कि सरकार ऐसा उद्योग विकसित करना चाहती है जो गतिशील हो और यह वैश्विक उद्योग में यह निरंतर अग्रणी रहे। उन्होंने कहा, 'एयरो इंडिया हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्प्रेरक बन सकता है। मैं यहां इसीलिए आया हूं।'

उन्होंने कहा, 'मेरे लिए यह सिर्फ रक्षा उपकरणों का व्यापार मेला नहीं है। यह सबसे बड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में से एक का सबसे विकसित प्रौद्योगिकियों और जटिल उपकरणों का महासम्मेलन है और भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को पेश करने का मंच है।' श्री मोदी ने कहा कि मजबूत रक्षा उद्योग वाला देश न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित होगा बल्कि इसके आर्थिक फायदे भी होंगे, निवेश बढेगा, विनिर्माण का प्रसार होगा, उद्यम को सहायता मिलेगी, प्रौद्योगिकी का स्तर बढेगा और देश में आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र में ही करीब दो लाख कामगार और हजारों इंजीनियर काम करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान से जुड़ने के लिए विदेशी कंपनियां एक दूसरे के साथ स्पर्धा कर रही हैं क्योंकि विदेशी कंपनियां अरबों डालर के फलते-फूलते भारतीय रक्षा बाजार में प्रवेश करना चाहती हैं। वैमानिकी और विमानन प्रदर्शनी के 10वें अंतरराष्ट्रीय संस्करण में कई देशों के 54 मंत्रीस्तरीय और अन्य उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने हिस्सा लिया। ■

पृष्ठ 7 का शेष...

अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि समाज के अत्यंत संवेदनशील एवं वंचित वर्गो के सर्वाधिक गरीब तबके को साथ लेते हुए वह सबका समेकित विकास करने को प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, ''समाज के अत्यंत संवेदनशील एवं वंचित वर्गो के सर्वाधिक गरीब तबके को साथ लेते हुए सबका समेकित विकास मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

8. स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी सात साल में 15 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी

स्वच्छ ऊर्जा सृजन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगले सात साल में देश में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 अति-वृहत सौर पार्को की स्थापना की योजना अनुमति दी गई है। हरित ऊर्जा गलियारा योजना के कार्यान्वयन को गति प्रदान की गई है।

9. रसोई-गैस सब्सिडी का सीधा भुगतान विश्व में अपने किस्म की सबसे बड़ी योजना

देश के 15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से करीब 75 प्रतिशत को सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में नकद किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर रसोई गैस खरीदने में मदद मिली है। इस तरह यह योजनाओं में लाभ के सीधे अंतरण (डीबीटी) का विश्व में सबसे बडा कार्यक्रम बन गया है।

10. ओलंपिक स्तर की प्रतिभाएं खोजने के लिए 'लक्ष्य ओलंपिक पोडियम' की शुरुआत

सरकार ने देश में शिक्षा का स्तर बढाने के साथ ही खेलकूद में भी विश्वस्तरीय प्रतिभाओं की तलाश के लिए 'लक्ष्य ओलंपिक पोडियम' के माध्यम से 8 से 12 वर्ष उम्र के बच्चों की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए 'राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना' तैयार की है। ■

संगठनात्मक गतिविधियां : सदस्यता महाभियान

31 मार्च के बाद विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी भाजपा : दिनेश शर्मा

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध हैं और वे उत्तर प्रदेश की राजधानी के महापौर है। वे भाजपा सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक भी है। 'कमल संदेश' के सम्पादकीय मंडल सदस्य राम प्रसाद त्रिपाठी से हुई बातचीत में उन्होंने सदस्यता अभियान को अत्यधिक सफल बताते हुए संगठन की उपलब्धियां सामने रखीं। उन्होंने निकट भविष्य में संगठन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी उल्लेख किया और इसकी सफलताओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि 31 मार्च के बाद भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी उभर कर आएगी। प्रस्तुत है मुख्य अंश :

लोकसभा की ऐतिहासिक विजय और राज्य विधानसभा के चुनावों में उसकी ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा ने राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान शुरू किया है, जिसमें कम से कम 10 करोड़ नए सदस्य बनाने की योजना है। किन्तु पार्टी इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएगी और इसका तंत्र क्या है?

पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 1 नवम्बर 2014 को राष्ट्रीय अभियान छेड़कर पार्टी में कम से कम तीन से चार गुणा तक प्राइमरी सदस्य बढ़ाने का संकल्प किया है। उन्होंने इसी दिन अपना मोबाईल फोन इस्तेमाल कर पार्टी की प्राइमरी सदस्यता ग्रहण की। विशेष बात यह है कि भाजपा ही देश में ऐसी राजनैतिक पार्टी है जो आरम्भ से ही हर छह वर्ष के बाद इस प्रकार का सदस्यता अभियान चलाती है। वर्तमान सदस्यता अभियान 31 मार्च 2015 तक चलेगा। आम आदमी की जबरदस्त भागीदारी से हमारा यह कार्यक्रम सफल होगा और हम अपने लक्ष्य को पार कर जाएंगे।

पहले की तरह ही, भाजपा बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चला रही है, परन्तु जहां तक अभियान तंत्र का संबद्ध है, पारम्परिक तौर-तरीकों के अलावा हम पहली बार नई तकनीक का प्रयोग कर रहे है और सदस्यों को मोबाईल फोन पर सदस्य बना रहे हैं।

कोई व्यक्ति किस प्रकार से भाजपा का प्राइमरी सदस्य बन सकता है और सक्रिय सदस्य बनने के लिए क्या प्रक्रिया है?

कोई भी व्यक्ति भाजपा का सदस्य बनने के लिए 18002662020 पर फोन करेगा। किन्तु 1 अप्रैल से हम 'सदस्यता महाभियान' चला रहे है और हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक प्राइमरी सदस्य के घर जाएंगे और उन्हें रजिस्टर करेंगे। योजना के अनुसार, अप्रैल और मई माह के दौरान हम प्रत्येक प्राइमरी सदस्य को 'पहचान पत्र' देंगे। जो लोग आपराधिक रिकार्ड के होंगे या जो भाजपा के सदस्य बनने के लिए उचित नहीं होंगे, उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा।

सक्रिय सदस्य बनने के लिए उसे कम से कम 100 प्राइमरी सदस्य बनाना आवश्यक है। पार्टी ने इस प्रयोजन के लिए उन्हें 'सदस्यता फार्म' जारी किया है और कार्यकर्ताओं को अपने 7 दिन के प्रवास में सदस्यता संख्या, व्यक्ति का नाम, उस प्राइमरी सदस्य का टेलीफोन नं. और पार्टी के मण्डल/जिला अध्यक्ष को इसे जमा कराना होगा। तभी वह सक्रिय सदस्य बन सकेगा/सकेगी।

सदस्यों को एनरोल करने के लिए मोबाइल टैक्नोलॉजी की शुरूआत करने के पीछे क्या तर्क है?

सर्वे रिपोर्टों के अनुसार भारत में 93 करोड़ से अधिक लोगों के पास मोबाइल हैं। इस प्रकार के आंकड़ों ने हमें अपने सदस्यों को एनरोल करने के लिए इस मोबाइल टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की प्रेरणा दी। पिछली बार डेढ़ वर्षों में हमने रसीद पुस्तकों के माध्यम से 3.7 करोड़ सदस्य बनाए थे। अत:, इस बार संगठन ने निर्णय लिया है कि हम मोबाइल के माध्यम से सदस्य बनाने की नई तकनीक का प्रयोग करेंगे। वास्तव में यह तकनीक बड़ी उत्साहजनक रही। 22 फरवरी 2015 तक भाजपा ने 5 करोड़ 70 लाख सदस्य रजिस्टर किए और लगभग 10 कराड़ फोन कॉल प्राप्त हुई। हमने इन कॉलों को सदस्य सूची में दर्ज किया है। अब भी 66 लाख लोगों ने रसीद पुस्तकों के माध्यम से सदस्यता ग्रहण की है। अब मोबाइल सदस्यता अभियान जारी है और हमें उम्मीद है कि इस टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हम कम से कम 3-4 गुणा सदस्यों की संख्या बढ़ा सकेंगे।

उन लोगों के लिए आपके पास क्या योजना है, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है? वे किस प्रकार से भाजपा के सदस्य बन सकते है?

हमने 'एक मोबाइल एक सदस्य' की व्यवस्था रखी है। यदि हम एक मोबाइल संख्या से अनेकानेक सदस्य बनाने की अनुमति देते हैं तो यह आंकड़ा कई गुणा बढ़ जाएगा। किन्तु, बिना मोबाइल वाले व्यक्तियों को फोन सं. 9242492424 पर एसएमएस भेजना होगा और वह भाजपा का/की सदस्य बन सकेगा/सकेगी। दूसरे, रसीद पुस्तक व्यवस्था द्वारा पारम्परिक सदस्यता ग्रहण करना जारी है। परन्तु हम उनकी सदस्यता पर बाद में विचार करेंगे।

अब तक सदस्यता अभियान का रिस्पांस क्या है?

कार्यक्रम शुरू करने के बाद पहले 30 दिनों में हमने 1 करोड़ सदस्य बनाए, फिर अगले 22 दिनों में हमने 1 करोड़ सदस्य बनाए, इसके बाद 13 दिनों, 15 दिनों, 16 दनों और 18 दिनों की अवधि में हमने प्रत्येक अवधि में क्रमश: 1 करोड़ सदस्य बनाए। इस प्रकार, सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा और दक्षिणी राज्यों में भाजपा के सदस्यों की संख्या ने सभी रिकार्ड तोड़ दिए है और इनमें भारी वृद्धि हुई है। इससे पहले, पश्चिम बंगाल में 1.5 लाख सदस्य थे। 1 नवम्बर के बाद और अब तक हमने 20 लाख नए सदस्य बनाए हैं। इसी प्रकार, कर्नाटक में हमारे 45 लाख, दिल्ली में 2.6 लाख, राजस्थान में 40 लाख, गुजरात में 60 लाख नए सदस्य बने हैं और अन्य दूसरे राज्यों में सदस्यों की संख्या उत्साहवर्धक है। इससे हमारे इस कार्यक्रम की सफलता और लोकप्रियता का पता चलता है।

जहां तक संख्या का संबंध है तो क्या भाजपा ने कोई लक्ष्य निधारित किया है?

हमने कोई लक्ष्य नहीं रखा है, परन्तु, हमारा लक्ष्य पार्टी की प्राइमरी सदस्यता अभियान को कम से कम 3-4 गुणा बढ़ाना है और सक्रिय सदस्यता में वर्तमान आंकड़ों से बढ़कर कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि करना है। अब इस समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वास्तविक सदस्यता लगभग 6.5 करोड़ है। किन्तु उन्होंने जबरदस्ती आर्मी, पुलिस सरकारी कर्मचारियों को सदस्य बनाकर इसे 8 करोड़ तक पहुंचा दिया है। एक बात निश्चित है कि 31 मार्च के बाद यह आंकड़ा कहीं अधिक बढ़ जाएगा और भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी होगी।

क्या पार्टी के पास प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना है, जिससे वह भाजपा की विचारधारा को नए सदस्यों में समावेश कर सके?

'सदस्यता महाभियान' के बाद पार्टी जून और जुलाई में नए सदस्यों और पार्टी के सक्रिय सदस्यों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण शिविर लगाएगी और हम भाजपा की विचारधारा उन तक पहुंचाएंगे।

31 मार्च को इस अभियान की समाप्ति के बाद क्या पार्टी की सदस्यता अभियान के विस्तार की कोई योजना है?

'यह-सदस्यता अभियान' 31 मार्च को समाप्त होगा। उसके बाद, संगठन ने पूरे वर्ष 2015 को 'सदस्यता पर्व वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य 'सदस्यता अभियान' को देश के घर-घर तक ले जाना है और पार्टी का अंतिम उद्देश्य है कि देश में 'घर-घर भाजपा' या हर घर में भाजपा का सदस्य हो।

किस प्रकार से भाजपा इतने बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान का आयोजन करती है और भाजपा का

शेष पृष्ठ 13 पर

लोग बढ़चढ़ कर सदस्यता अभियान में भाग ले रहे हैं : अरुण सिंह

'कमल संदेश' के सम्पादकीय मंडल सदस्य राम प्रसाद त्रिपाठी ने सदस्यता अभियान के बारे में भाजपा राष्ट्रीय सचिव और सदस्यता अभियान के सह-संयोजक श्री अरुण सिंह से बातचीत की। कतिपय प्रमुख अंश उद्धृत है :

सदस्यता अभियान चलाने के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल के पीछे क्या तर्क हैं और किस प्रकार से इससे कार्यकर्ताओं को लाभ मिलता है ?

भारत में लोगों के एक बड़े हिस्से के पास मोबाइल फोन हैं। इसी कारण, मोबाइल फोन पर सदस्यों को एनरोल करने के पीछे यही उद्देश्य रहा है कि समाज के सभी स्तरों के लोगों को एक मंच प्रदान किया जाए कि वे अपनी मनमर्जी से पार्टी में शामिल हों और वे अपने मोबाइल से मात्र एक 'मिसकॉल' दे सकते हैं।

दूसरे, इस प्रकार के अभियान से भाजपा को कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा ऑन लाइन डाटा आधार मिल जाएगा, जिससे पार्टी मजबूत होगी तथा एक ही समय में देश के सभी भागों में सूचना फैलाई जा सकेगी।

तीसरे, किसी भी समय भाजपा नेतृत्व सीधे बूथ-स्तर पर कार्यकर्ताओं से सम्पर्क कर सकता है और वे पार्टी का संदेश भेजा जा सकते है तथा सरकार की उपलब्धियां भी उन्हें प्रदान की जा सकती हैं और इस प्रकार जमीनी स्तर पर उनका फीडबैक प्राप्त हो सकता हैं। परिणामस्वरूप, दोनों तरफ से संवाद संभव हो सकता है।

चौथे, बिना किसी भेदभाव के कोई भी व्यक्ति पार्टी का सदस्य बन सकता है और आखिरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार वे अभियान से कार्यकर्ताओं के मन में पार्टी से जुड़ने की भावना भी पैदा हो सकेगी।

क्या नए सदस्यों को भाजपा की विचारधारा से शिक्षित करने की भी कोई योजना है ? क्या आप इस पर और अधिक प्रकाश डालेंगे ?

सदस्यता अभियान के बाद 1 अप्रैल से हम पूरे देश में महा संपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को सदस्यता पहचान पत्र दिया जाएगा और मई तक हम अपने सभी प्राइमरी सदस्यों की सूचना इकट्ठी कर लेंगे। जून और जुलाई में हम देश के लगभग 15 लाख नए सक्रिय सदस्यों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे। हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम को तीन भागों में बांटा है।

पहले भाग में पार्टी की विचारधारा को रखा गया है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, श्री सुन्दर सिंह भंडारी, राजमाता विजयराजे सिंधिया, श्री जगन्नाथ राव जोशी और श्री नानाजी देशमुख के बलिदान और परिश्रम के कारण पार्टी मजबूत बन पाई है। निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप बहुत से वरिष्ठ नेताओं जैसे, आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी के कारण हम इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। हम अपने वरिष्ठ नेताओं के कामों को आगे ले जाएंगे और उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने सदस्यों को विचारधारा तथा उनके कामों से अवगत कराएंगे।

दूसरे भाग में हम सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। और

अपने आखिरी भाग में हम कार्यकर्ताओं के विकास तथा कार्यकर्ताओं के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

इस अभियान पर लोगों का जवाब क्या है ?

मोबाइल पर सदस्यता एक नूतन विचार है। अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के सदस्य बन सकता है। पारम्परिक ढंग के अलावा 'मिस्डकॉल' की संख्या बढ़ाकर हम सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें ट्विटर, फेसबुक और फोन संदेश का प्रयोग शामिल है। इसके

लिए हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं को भी विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये कार्यकर्ता गांवों, रेलवे प्लेटफार्मों, बस स्टैण्डों तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाकर भाजपा सदस्यता अभियान के बारे में लोगों को बता रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता सराहनीय है और यह कार्यक्रम उन्हीं की सक्रियता से सफल होगा।

जहां तक लोगों के रिस्पांस का सवाल है, आम लोग अत्यंत रूचि ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा और दक्षिणी राज्यों में भाजपा की सदस्यता ने सभी रिकार्ड तोड़ डाले हैं और इसमें लगभग 10 से 20 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। हमें उम्मीद है कि यह अभियान सभी पुराने रिकार्ड तोड़ेगा और भाजपा को विश्व की सबसे बड़ा राजनैतिक संगठन बनाएगा। ■

पृष्ठ 11 का शेष...

कार्यकर्ता इसमें अपना कितना सहयोग दे सकता है?

विश्व की किसी भी राजनैतिक पार्टी का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान होता है। अत: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह इस कार्यक्रम पर निगाह रख रहे हैं और इस प्रयोजन के लिए हर राज्य में जा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूं और मैं 18 राज्यों में जा चुका हूं। भाजपा सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय सह-संयोजक, अर्थात् डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, श्री अरुण सिंह, श्री सीटी रवि और श्रीमती सुधा यादव भी प्रभागीय और जिला स्तर के शहरों और विभिन्न राज्यों के कस्बों में जाकर बैठकें आयोजित कर रही है। इसी प्रकार, प्रत्येक राज्य में हमारे संयोजक और सह-संयोजक हैं, जो मण्डल स्तर तक इनका आयोजन करते हैं। किन्तु हम कार्यकर्ताओं को अधिकाधिक सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमने निर्णय लिया है कि जो कार्यकर्ता 1000 से अधिक सदस्य बनाएंगे, उनका राज्य स्तर पर अभिवादन किया जाएगा। और जो 5000 से अधिक सदस्य बनाएंगे, जैसे राजस्थान के श्री सागर जोशी (अकेले 15,000 सदस्य बनाए) और श्री सी.आर. पाटिल, एम.जी, सूरत, गुजरात जिन्होंने (6000 सदस्य बनाए), उन्हें संगठन केन्द्रीय स्तर पर अभिवादन करेगा। वास्तव में, यह पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है और इससे निश्चित ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन सकेगी। ■

श्रद्धांजलि

वरिष्ठ भाजपा नेता हरीशचंद्र श्रीवास्तव नहीं रहे

भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री हरीशचंद्र श्रीवास्तव का 18 जनवरी 2015 को निधन हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने दिवंगत नेता के बेटे श्री सौरभ श्रीवास्तव से फोन पर बातचीत की और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।

श्री भारद्वाज ने बताया कि 90 साल के श्री हरीशचंद्र श्रीवास्तव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका हरीशचंद्र घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। श्री श्रीवास्तव वाराणसी से तीन बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। वह साल 1977 में जनता पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे।

गोरखपुर के मनिकपुर गांव में 1925 में जन्मे श्री श्रीवास्तव पहली बार वहीं से विधायक निर्वाचित हुए थे। उनके परिवार में पत्नी श्रीमती ज्योत्सना, एक बेटा और एक बेटी हैं। श्रीमती ज्योत्सना वाराणसी की छावनी सीट से भाजपा विधायक हैं। ■

'सब को काम' ही भारतीय अर्थनीति का एकमेव मूलाधार

– दीनदयाल उपाध्याय

बेकारी की समस्या यद्यपि आज अपनी भीषणता के कारण अभिशाप बनकर हमारे सम्मुख खड़ी है किंतु उसका मूल हमारी आज की समाज, अर्थ और नीति व्यवस्था में छिपा हुआ है। वास्तव में जो पैदा हुआ है तथा जिसे प्रकृति ने अशक्त नहीं कर दिया है, काम पाने का अधिकारी है। हमारे उपनिषद्कार ने जब यह घोषणा की कि 'काम करते' हुए हम सौ वर्ष जीएँ (कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत् समारू।) तो वे यही धारणा लेकर चले कि प्रत्येक को काम मिलेगा इसीलिए शास्त्रकारों ने प्रत्येक के लिए कर्म की व्यवस्था की। यहाँ तक कि इस आशंका से कि कोई कर्महीन रहकर केवल भोग की ही ओर प्रवृत्त न हो जाए उन्होंने यह धारणा प्रचलित की कि यह भारतभूमि 'कर्मभूमि' है। स्वर्ग के देवता भी अपने कर्म फल क्षय हो जाने पर यही इच्छा करते हैं कि वे भारत में जन्म लें एवं पुन: सुकृत संचय करें। तात्पर्य यह कि हमने किसी भी व्यक्ति के संबंध में बेकारी अथवा कर्म विहीनता की कल्पना नहीं की। अत: भारतीय अर्थनीति का आधार 'सबको काम' ही हो सकता है। बेकारी अभारतीय है। भारतीय शासन का कर्तव्य है कि वह इस आधार को लेकर चले।

बेकारी के कारण

लोगों को काम न मिलने के दो ही कारण हैं। प्रथम, तो काम के लिए जिस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता हो, वैसी योग्यता उनमें न हो। दूसरे, काम करनेवालों का इतना बाहूल्य हो कि उद्योग धंधे, व्यापार एवं सार्वजनिक सेवाओं का वर्तमान स्तर उन्हें खपा न

पाएँ। बेकारी के अन्य कारण भी हैं किंतु वे तात्कालिक एवं अस्थायी हैं। भारत में आज दोनों ही कारण उपस्थित हैं। अत: बेकारी के प्रश्न को हल करने के लिए हमें इनके संबंध में गंभीरता से विचार करना होगा। शिक्षा की पद्धति और उद्योग धंधों के विकास के संबंध में अपनी नीति निश्चित करनी होगी। इस नीति के साथ बेकारी को दूर करने का प्रश्न ही नहीं, देश की समृद्धि का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है।

अर्थ-नीति का आधार

भारत की जनसंख्या, उसके सात लाख गाँव, उसका विस्तार, भारतीय जन की प्रकृति, हमारी समाज-व्यवस्था, युगों से चली आई हमारी अर्थ-नीति की परंपरा आदि का विचार कर आज सभी अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि भारतीय समृद्धि का आधार हमारे कुटीर एवं ग्रामोद्योग ही हो सकते हैं। हाँ, यूरोपीय अथवा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक कुछ अपवादस्वरूप व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे जो इन उद्योगों में मध्ययुगीन संस्कृति की बू पाते हैं तथा जो इन्हें अप्रगतिशील मानकर इंग्लैंड और अमेरिकी पद्धति पर बड़े-बड़े कल-कारखाने खोलने की सलाह देते हैं। यद्यपि यह बात सत्य है कि किसी भी दिशा में अतरेककर अंतिम कोटि का विचार प्रस्तुत करना बुद्धिमानी नहीं होगी। फिर भी हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था का कोई केंद्र अवश्य निश्चित कर लेना होगा जिसके चारों ओर एवं जिसके हित-संवर्धन में बड़े पैमाने पर उद्योगों को हम अपना केंद्र बनाएँ? आज इस दृष्टि से हमारी स्थिति बहुत ही गिरी हुई है। दूसरे देशों के मुकाबले में बड़े उद्योगों में हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। यदि उस दृष्टि से हम कुछ करना चाहें तो हमें मशीन और तंत्र-विशारदों के लिए ही नहीं बल्कि पूँजी के लिए भी दूसरे देशों का मुँह ताकना पड़ेगा। पिछले छह वर्षों से हम यही करते आ रहे हैं और अपना करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा चुके हैं। हमें जन-शक्ति की दृष्टि से भी विचारना

होगा। इन बड़े कारखानों में यदि हजारों को काम मिलता है तो दूसरी ओर लाखों बेकार हो जाते हैं।

यदि कल्पना कर भी ली जाए कि संपूर्ण भारत में बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण होने पर चारों ओर सुख और समृद्धि लौटने लगेगी किंतु जब तक हम अपने को पूरी तरह उजाड़ चुके होंगे। इस परिवर्तन में करोड़ों नष्ट हो जाएँगे तथा संभव है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने के पूर्व ही जन-क्षोभ की ज्वाला में भस्म हो जाएँ। अत: हमारा केंद्र तो होना चाहिए मनुष्य। मनुष्य को काम मिले और वह सुखी रहे यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मशीन मनुष्य की सुविधा के लिए है, उसका स्थान लेने के लिए नहीं। मनुष्य मशीन का निर्माता है, उसका स्वामी है, उसका गुलाम नहीं। उत्पादन के साधन की दृष्टि से उसका उपयोग अवश्य है किंतु वह मनुष्य को खाकर नहीं उसे खिलाकर होना चाहिए। इस दृष्टि से मनुष्य श्रम और मशीन में एक समन्वय चाहिए जो प्रत्येक समाज धीरे-धीरे करता जाता है। ज्यों-ज्यों उद्योगों की अवस्था में उन्नति होती जाती है, उनको बाजार मिलता जाता है, मनुष्य स्वयं मशीनों का सहारा लेता है। किंतु जब यही अस्वाभाविक रूप से किया जाता है तो हानि होती है। अत: भारत में कुटीर और ग्रामोद्योग ही हमारे केंद्र हो सकते हैं। बड़े-बड़े उद्योग इन उद्योगों के हित में जहाँ चलाना आवश्यक हो चलाए जाएँ किंतु इनके प्रति स्वार्थी बनकर नहीं।

औद्योगीकरण कैसे?

आवश्यकता है कि वेग के साथ औद्योगीकरण का कार्यक्रम अपनाया जाए। इसके लिए कुटीर एवं ग्रामोद्योगों को आधार बनाकर, बड़े उद्योगों को उनके साथ समन्वित किया जाए। वे एक-दूसरे के प्रति स्पर्धी न बने इसका ध्यान रखा जाए। इस दृष्टि से कुछ सुझाव नीचे दिए जाते हैं

केंद्र में एवं प्रांतों में उन उद्योगों के रक्षण एवं विकास के लिए आयोगों की स्थापना हो।

छोटे उद्योगों को कच्चा माल दिलाने की पूर्ण व्यवस्था की जाए। सहकारी संस्थाओं की स्थापना करके अथवा पुरानी आढ़त की पद्धति का प्रचार करके यह व्यवस्था की जा सकती है। सरकार अपनी ओर से गोदाम खोल सकती है।

कारीगरों को कम दर पर कर्जा मिलने की व्यवस्था हो।

छोटी मशीनें जो विद्युत् से भी चल सकें उन्हें उपलब्ध कराई जाएँ तथा उन्हें विद्युत् शक्ति देने का प्रबंध हो।

मशीन और कच्चा माल अगाऊ मिल सके तथा उसका भुगतान तैयार माल से अथवा किश्तों में हो।

तैयार माल की बिक्री के लिए उचित व्यवस्था हो। सहकारी संस्थाओं के द्वारा अथवा सहकारी क्रय भंडारों द्वारा यह व्यवस्था हो। सरकार इस बात का दायित्व ले कि वह कारीगरों द्वारा तैयार माल को, यदि वह बाजार में नहीं बिकता, तो उचित मूल्य पर खरीद लेगी।

- स्थान-स्थान पर इन उद्योगों की दृष्टि से अनुसंधान केंद्र खोले जाएँ।
- रेल भाड़े की दरों में कुटीर उद्योगों के माल के अनुरूप परिवर्तन किया जाए।
- बड़े कारखाने केवल उन वस्तुओं के खोले जाएँ जिनका विकेंद्रीकरण संभव न हो, इनके उत्पादन की सीमाएँ एवं क्षेत्र, निश्चित कर दिए जाएँ।
- विदेशी माल पर नियंत्रण कर स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया जाए।
- सरकारें अपनी आवश्यकता की पूर्ति कुटीर उद्योगों के माल से ही करें।
- कारीगरों को शिक्षा देने के लिए उद्योग शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए।
- कुटीर उद्योगों के माल को बिक्री कर आदि करों से मुक्त कर दिया जाए।
- दूतावासों में केवल स्वदेशी तथा विशेषत: कुटीर उद्योग निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग हो।

बेकारी को रोकने एवं उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने के लिए सर्वसाधारण की क्रयशक्ति बढ़नी चाहिए। इसके लिए आय की विषमता दूर कर उसमें समानता स्थापित करनी होगी। शासन की कर-नीति इस लक्ष्य की प्राप्ति में दूर तक नहीं ले जाती। निम्न और मध्यवर्ग के लोगों को कर मुक्त कर ऊपर के वर्ग पर कर का भार बढ़ाना होगा। बड़े-बड़े लोग पूँजी के दब जाने का शोर मचाकर भार से बचते रहते हैं

आवश्यकता है कि वेग के साथ औद्योगीकरण का कार्यक्रम अपनाया जाए। इसके लिए कुटीर एवं ग्रामोद्योगों को आधार बनाकर, बड़े उद्योगों को उनके साथ समन्वित किया जाए। वे एक-दूसरे के प्रति स्पर्धी न बने इसका ध्यान रखा जाए।

किंतु यह ठीक नहीं। यदि आर्थिक विषमता बनी रही तथा नीचे के लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी तो पूँजी निकालकर भी कोई लाभ नहीं। वास्तव में तो जो चीज पैदा होती है उसके खरीददार मिलते गए तो उद्योग पनपता जाएगा। अत: पैदा किए हुए माल के लिए माँग पैदा करना उद्योगों को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इस माँग की कमी के कारण ही बेकारी पैदा होती है।

औद्योगिक शिक्षा

अक्षर और साहित्य ज्ञान के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थी को किसी न किसी प्रकार की औद्योगिक शिक्षा दी जाए। औद्योगिक शिक्षा की दृष्टि से यद्यपि विचार बहुत दिनों से हो रहा है किंतु अभी तक सिवाय कुछ औद्योगिक शिक्षा केंद्रों के खोलने के साधारण शिक्षा का मेल औद्योगिक शिक्षा से नहीं बैठाया गया है। टेक्निकल और वोकेशनल शिक्षा केंद्रों में भी शिक्षा प्राप्त नवयुवक इस योग्य नहीं बन पाते कि वे स्वयं कोई कारोबार शुरू कर सकें। वे भी नौकरी की ही तलाश में घूमते हैं। कारण, जिस प्रकार की शिक्षा उन्हें दी जाती है वह उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के अयोग्य बना देती है। अत: आवश्यक तो यह होगा कि गाँवों के धंधे, खेती और व्यापार के साथ हमें शिक्षा का मेल बैठाना होगा। प्रथमत: शिक्षा की प्रारंभिक एवं माध्यमिक अवस्थाओं में हमें विद्यार्थी को उसके घरेलू धंधे के वातावरण से अलग करने की जरूरत नहीं। बल्कि हम ऐसा प्रबंध करें कि वह उस वातावरण में अधिक-से-अधिक रह सके तथा अज्ञात रूप से वह धंधा सीख सके। धीरे-धीरे हमें यह भी प्रयत्न करना होगा कि वह अपने अभिभावकों का सहयोगी बन सके। माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने तक नवयुवक को अपना धंधा भी आ जाना चाहिए। हो सकता है कि उन धंधों की योग्यता के प्रणामपत्र की भी हमें कुछ व्यवस्था करनी पड़े। माध्यमिक शिक्षा तक कुशाग्र बुद्धि सिद्ध होनेवाले नवयुवकों की आगे शिक्षा का प्रबंध उनकी रुचि के अनुसार किया जाए।

अक्षर और साहित्य ज्ञान के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थी को किसी न किसी प्रकार की औद्योगिक शिक्षा दी जाए। औद्योगिक शिक्षा की दृष्टि से यद्यपि विचार बहुत दिनों से हो रहा है किंतु अभी तक सिवाय कुछ औद्योगिक शिक्षा केंद्रों के खोलने के साधारण शिक्षा का मेल औद्योगिक शिक्षा से नहीं बैठाया गया है। टेक्निकल और वोकेशनल शिक्षा केंद्रों में भी शिक्षा प्राप्त नवयुवक इस योग्य नहीं बन पाते कि वे स्वयं कोई कारोबार शुरू कर सकें। वे भी नौकरी की ही तलाश में घूमते हैं। कारण, जिस प्रकार की शिक्षा उन्हें दी जाती है वह उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के अयोग्य बना देती है। अत: आवश्यक तो यह होगा कि गाँवों के धंधे, खेती और व्यापार के साथ हमें शिक्षा का मेल बैठाना होगा।

जनसंख्या उसकी आवश्यकता में उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन एवं व्यवस्था, इन तीनों का पारस्परिक संतुलन जब बिगड़ जाता है तब अर्थ-संबंधी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। आज देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है किंतु उसके अनुपात में उत्पादन के साधन और उत्पादन नहीं बढ़ रहा। फलत: हमारी आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं हो पातीं। अत: हमारा रहन-सहन स्तर बहुत ही नीचा है। निष्कर्ष यह निकलता है कि हम उत्पादन के साधनों की वृद्धि के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करें। इसके लिए हमारी निगाह स्वाभाविक ही पश्चिम के बड़े-बड़े कारखानों के द्वारा उत्पादन की ओर चली जाती है और हम पिछले छह वर्षों से उसके लिए प्रत्यनशील हैं। किंतु प्रश्न उठता है कि क्या उन साधनों से हम देश के सभी लोगों को काम दे सकेंगे यदि नहीं तो उन साधनों के स्वामी एवं उनपर काम करनेवाला एक छोटा सा वर्ग रह जाएगा। फलत: उत्पादित वस्तुओं का समान रूप से वितरण नहीं होगा। बचे हुए लोगों को या तो जनसेवा के रूप में लगाना होगा अथवा हमारी आवश्यकताएँ इतनी विभिन्न प्रकार की हो जाएँ जिससे उसकी पूर्ति के लिए सबको खपा सकें तथा उनके साधन जुटा सकें। यह भी संभव है कि हम कानून बनाकर जहाँ चार लोगों से काम चल जाएँ वहाँ दस लोगों को रखने की सलाह दें यह प्रजातांत्रिक देश में व्यापक रूप से संभव नहीं है। आज बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना के साधन जुटाना भी हमारे लिए कठिन हो रहा है तथा उस प्रतिक्रिया में हम छोटे उद्योगों के साधनों को भी नष्ट कर रहे हैं। अब बेकारी प्रमुखतया यांत्रिक है। यंत्र मनुष्य की जगह लेता जा रहा है तथा मनुष्य बेकार होता जा रहा है। यंत्र का अर्थ प्रगति समझा जाता है और इसलिए हमारी प्रगतिवादी मनोवृत्ति यंत्रीकरण से विमुख नहीं होने देती। हमें इस संबंध में समन्वयात्मक दृष्टि से

काम करना होगा। हमारी नीति का आधार होना चाहिए प्रत्येक को काम।

प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि उसे काम मिले। काम न मिलने से उसकी व्यक्तिगत आजीविका का सहारा तो जाता ही रहता है, वह राष्ट्र की संपत्ति के अर्जर में सहायता देने से भी वंचित हो जाता है। प्रत्येक को काम का सिद्धांत यदि स्वीकार कर लिया तो श्समवितरणश की दिशा में निश्चित हो जाती है। अधिक केंद्रीकरण के स्थान पर हम विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ते जाते हैं।

ज X क X य = इ

प्रत्येक को काम का सिद्धांत स्वीकार करने पर बाकी बातों का भी निर्धारण हो सकता है। गणित के छोटे से सूत्र के रूप में हम अर्थशास्त्र का यह सिद्धांत रख सकते हैं

ज X क X य = इ

यहाँ 'इ' समाज की प्रभावी इच्छा का द्योतक है जिसकी पूर्ति की उसमें शक्ति है।

'ज' समाज के काम करने योग्य व्यक्तियों का द्योतक है।

'क- काम करने की अवस्था एवं व्यवस्था का द्योतक है।

'य' यंत्र का द्योतक है।

इस सूत्र के अनुसार यदि हम चाहते हैं कि 'ज' निश्चित रहे तो 'इ' के अनुपात में 'क' और 'य' को बदलना होगा। ज्यों-ज्यों हमारी माँग बढ़ती जाएगी हमें ऐसे यंत्रों का उपयोग करना होगा जिनके सहारे हम अधिक उत्पादन कर सकें। आज शासन जिस नीति पर चल रहा है उसमें 'य' सबका नियंत्रण कर रहा है।

वास्तव में तो 'इ' प्रभावी माँग के बढ़ने से ही हमारी समस्या हल होगी किंतु 'इ' सहज ही नहीं बढ़ सकती क्योंकि यह हमारी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। अत: शासन को देश की क्रय शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न भी करना होगा।

'इ' अर्थात् प्रभावी माँग देश में तथा देश के बाहर भी हो सकती है। यदि हमारा माल बाहर जाता है तो 'इ' बढ़ जाती है। बाहर से माल आने पर देशज वस्तुओं की दृष्टि से 'इ' कम हो जाती है क्योंकि हमारी कार्य-शक्ति का बहुत बड़ा भाग बाहर से आई वस्तुओं की खरीद पर खर्च हो जाता है। आज यही हो रहा है। सरकार की आयात-नीति के कारण हमारे बाजार विदेशी माल से पट गए हैं। उनके सस्ते और अच्छे होने तथा 'स्वदेशी' प्रेम के अभाव के कारण उनकी भारी खपत है। फलत: स्वदेशी वस्तुओं के लिए 'इ' दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है। चूँकि 'य' और 'क' में एकाएक परिवर्तन करना संभव नहीं इसलिए 'ज' कम होता जा रहा है। बेकारी बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए जहाँ एक ओर विदेशी आयात की उन वस्तुओं पर जो स्वदेशी तैयार माल पर अनुचित रूप से दबाव डाल रही हों प्रतिबंध लगाना होगा तो हमारी ओर समाज में 'स्वदेशी' की भावना को भी जाग्रत करना होगा। विदेशी आयात पर नियंत्रण आयात-निर्यात एवं तटकर नीति के द्वारा किया जा सकता है। बड़े-बड़े उद्योगों को संरक्षण देने की नीति तो शासन में अंग्रेजी काल से ही अपनाई है। घरेलू ग्रामोद्योगों की ओर इस दृष्टि से कभी ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें संरक्षण की नितांत आवश्यकता है और वह हमें देना ही होगा।

'इ' को बढ़ाने की दृष्टि से विदेशी व्यापार की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारी बहुत सी चीजों की विदेशों में खपत है। लड़ाई के जमाने में कपड़ा एवं कई अन्य वस्तुओं के लिए हमने मध्यपूर्व एवं सुदूरपूर्व के देशों में अपने बाजार बना लिए थे। काम की वस्तुओं के लिए तो आज भी अमेरिका और यूरोप के देशों में हमारे माल की काफी पूछ होती है। यदि प्रयत्न किया जाए तो ये बाजार भी बढ़ सकते हैं। फर्रुखाबाद की छींट और बनारस के रेशम के रुमालों की अमेरिका में बहुत भारी माँग है। किंतु सरकारी नियंत्रण नीति के कारण यह माँग ठीक तरह से पूरी नहीं हो पाई जबकि हम डालर कमाने के लिए बड़े उत्सुक रहे।

बड़े-बड़े उद्योगों को संरक्षण देने की नीति तो शासन में अंग्रेजी काल से ही अपनाई है। घरेलू ग्रामोद्योगों की ओर इस दृष्टि से कभी ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें संरक्षण की नितांत आवश्यकता है और वह हमें देना ही होगा।

'ज' अर्थात् देश की जनसंख्या तो हमारे देश में बराबर बढ़ती जा रही है। उसे सहसा रोका नहीं जा सकता। अत: 'इ' की वृद्धि के अनुपात में हमको 'क' और 'य' पर नियंत्रण करना होगा। आज देश में दो प्रकार के वर्ग हैं। एक तो आधुनिक यंत्रीकरण के बिलकुल विरोधी है तथा उसे कतई नहीं चाहते। दूसरे वे हैं जो अनियंत्रित रूप से यंत्रीकरण की वृद्धि चाहते हैं। हम समझते हैं दोनों ही दृष्टिकोण गलत हैं। जैसाकि ऊपर के सूत्र से ज्ञात होगा 'य' ध्रुव नहीं, बल्कि 'इ' तथा अन्य तत्त्वों पर अवलिंबत है। यदि हमारी 'इ' हमारी बढ़ गई कि बिना यंत्रों की वृद्धि के हम उसे पूरा नहीं कर सकते तो हमें यंत्रीकरण करना ही होगा

किंतु यदि माँग के बढ़े बिना हमने यंत्रीकरण करना स्वीकार कर लिया तो फिर 'ज' या 'क' में कमी करनी होगी। चूँकि 'क' को कम करना उत्पादन व्यय, समाज नीति आदि अनेक बातों पर निर्भर है, 'ज' कम हो जाएगा। अत: हमारा सिद्धांत है कि ज्यों-ज्यों देश की क्रय शक्ति एवं प्रभाव माँग बढ़ती जाए हम यंत्रों का अधिकाधिक उपयोग करते जाएँ। इस पद्धति में हमारा स्वाभाविक विकास होगा तथा हो सकता है कि हम अपनी स्थिति के अनुकूल अधिक उपयोगी यंत्रों का आविष्कार और निर्माण भी कर सकें।

क्या किया जाए?

बेकारी के इन कारणों को दूर करके समस्या को मौलिक रूप से हल करने के साथ ही आज जो बेकार हो गए हैं अथवा हो रहे हैं उनको फिर से काम देने की तथा जब तक काम नहीं मिलता तब तक उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। आज के बेकारों में बहुत बड़ी संख्या पढ़े-लिखे लोगों की है। उनको खपाने के लिए स्कूल खोलने की नीति सरकार ने अपनाई है। इस नीति को और भी व्यापक करना होगा।

स्कूल और कॉलेजों में तुरंत ही औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध कर देना चाहिए। जो 'अंतिम परीक्षा' पास करके निकलनेवाले हैं उनके लिए एक वर्ष की औद्योगिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। इससे पढ़े-लिखे बेकारों की समस्या के हल की दौड़ में एक वर्ष तुरंत आगे बढ़ जाएँगे तथा संभव है कि एक वर्ष की औद्योगिक शिक्षा प्राप्त नवयुवकों में से बहुत से लोग बाबूगिरी की और न दौड़कर हाथ से रोजी कमाना शुरू कर दें।

युद्धकाल में कारखानेदारों को भारी मुनाफा हुआ था जो आजकल संभव नहीं है। अत: आज गिरे हुए मुनाफों को हानि की आशंका से चारों ओर बचन की योजनाएँ प्रारंभ हो गई है जिसका परिणाम मजदूरों पर भी पड़ता है। उनकी छटनी की जा रही है। सरकार भी अपने विभिन्न विभागों में छटनी कर रही है। कई विभागों का जैसे रसद और पूर्ति विभाग तथा युद्धकालीन अनेक विभागों का काम अब समाप्त हो गया है। उनके कर्मचारियों की भी छटनी अनिवार्य सी प्रतीत होती है। ये बेकारी समस्या को और भी भीषण बनाए हुए हैं। आवश्यकता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को जब तक कहीं दूसरी नौकरी न मिल जाए उनकी जीविका की व्यवस्था की जाए। यूरोप के कई देशों में बेकारी बीमा योजना चालू है। अनैच्छिक रूप से बेकार होनेवाले श्रमिकों को इस योजना के अंतर्गत सहायता मिलती है। भारत सरकार के श्रममंत्री श्री गिरि ने एक त्रिदलीयमिल मालिक, श्रमिक और शासन के बीच समझौता कराता है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के अनिच्छा से काम से अलग होने पर उसे पैंतालीस दिन तक अपने वेतन एवं महँगाई भत्ता का आधा मिलता रहेगा। इस संबंध में एक विधान भी लोकसभा में प्रस्तुत होने की आशा है। यह पग ठीक दिशा में उठाया गया है। किंतु मालिकों के ऊपर यह भार न छोड़कर शासन को इसकी अलग से व्यवस्था करनी चाहिए तथा मालिकों से इस बीमा योजना में चंदा लेना चाहिए। साथ ही पैंतालीस दिन की अवधि न रखकर यह अवधि जब तक दूसरी नौकरी न मिले तब तक की रखनी चाहिए।

पढ़े-लिखे तथा लोगों की शिक्षा के औद्योगिक शिक्षा केंद्र खोले जाएँ जहाँ वे शिक्षा के साथ-साथ काम भी कर सकें। ये केंद्र सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर खोले जाने चाहिए।

गाँवों की बेकारी को दूर करने के लिए सहायता कार्य प्रारंभ किए जाएँ। सड़के, इमारतें, बाँध, कुएँ और तालाब आदि की बहुत सी योजनाएँ शुरू की जा सकती हैं। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भी जो योजनाएँ हैं उनमें जन-शक्ति का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। अभी तो वहाँ भी श्रम बचानेवाली बड़ी-बड़ी मशीनों का ही उपयोग किया गया है।

अर्थ-नीति के निर्धारण में शासन का प्रमुख हाथ होने के कारण उसकी नीति से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी और क्षमता बहुत अंशों में उसकी होती है। फिर भी जनता और राजनीतिक पार्टियाँ उस दृष्टि से अपने सीमित क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकती हैं। शासन को समस्या की गंभीरता का अनुभव कराने के लिए वे आंदोलन तो कर ही सकती हैं किंतु अपनी ओर से रचनात्मक सहयोग भी दे सकती है।

अपने क्षेत्र के छोटे-छोटे उद्योगों की तालिका बनाकर उनमें शिक्षार्थी के रूप में एक-एक, दो-दो व्यक्तियों को रखा जा सकता है। आज बहुत से कारोबार ऐसे हैं जिनमें रोजी कमाई जा सकती है। हाँ सीखे हुए लोगों की कमी है।

छोटे-छोटे उद्योग केंद्र भी सहकारी आधार पर चलाए जा सकते हैं। स्वदेशी की भावना एवं पारस्परिक संबंधों के सहारे उनके लिए बाजार भी मिल सकता है। इनके अतिरिक्त और भी रचनात्मक कार्य हाथ में लिए जा सकते हैं। ■

(पांचजन्य, 31 अगस्त, 1953)

अरुणाचल को आज 'गति' और 'ऊर्जा' दोनों ही मिल रही हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को आज गति और ऊर्जा दोनों ही मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि केवल नारों के सहारे ही गरीबी का उन्मूलन नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लांच की जा रही परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और बिजली सुलभ होगी, जो आगे चलकर गरीबी के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण हथियार बन जाएंगी।

गत 20 फरवरी को प्रधानमंत्री हरमुति-नाहरलगुन रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करने के बाद इटानगर में उपस्थित विशाल जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने नाहरलगुन एवं नई दिल्ली के बीच एसी एक्सप्रेस और नाहरलगुन एवं गुवाहाटी के बीच इंटर-सिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रधानमंत्री ने अरुणाचल महोत्सव 2015 का उद्घाटन किया और अरुणाचल प्रदेश के 29वें स्थापना दिवस पर एक स्मारिका जारी की। उन्होंने इटानगर के लिए एक जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया और 132 केवी की पारेषण लाइन की आधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अल्प विकास का सबसे बड़ा कारण कमजोर कनेक्टिविटी है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी बेहतर करने में योगदान देंगी।

प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में निहित विशाल पनबिजली संभावनाओं का जिक्र किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नेपाल और भूटान अपनी अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव के लिए किस तरह से पनबिजली का दोहन कर रहे हैं।

उन्होंने मिसाल देते हुए यह भी कहा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश ने भारत में यही कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश समूचे देश को बिजली मुहैया करा सकता है। उन्होंने इस राज्य की पनबिजली संभावनाओं का दोहन करने और इसके साथ ही पनबिजली परियोजनाओं के चलते विस्थापित होने वाले लोगों को समुचित मुआवजा देने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में छह नए कृषि विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विश्व भर में प्रसिद्ध जैविक खेती का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एफएम रेडियो सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'मेक इन नॉर्थईस्ट' को 'मेक इन इंडिया' का अभिन्न हिस्सा बनाने पर विचार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारीगण पूर्वोत्तर राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि विकास की राह की बाधाएं दूर हो सकें।

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जरनल निर्भय शर्मा (सेवानिवृत्त), अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नबम तुकी, केंद्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजीजू भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राजस्थान

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभांरभ

'स्वस्थ धरा, खेत हरा'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में कृषि क्षेत्र में मिट्टी की सेहत पर ध्यान देने का आह्वान किया, ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके और समृद्धि लाई जा सके।

गत 19 फरवरी को प्रधानमंत्री राजस्थान के सूरतगढ़ में केन्द्र सरकार की देशव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभांरभ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीबी मिटाने के लिए कृषि महत्वपूर्ण है। उन्होंने वन्दे मातरम गान की चर्चा करते हुए कहा कि भूमि को सुजलाम-सुफलाम बनाने के लिए मिट्टी का पोषण आवश्यक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इस दिशा में लाई गई है।

प्रधानमंत्री ने मिट्टी के नियमित परीक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि छोटे शहरों में भी उद्यमी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर सकते हैं।

उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और हाल में लांच की गई 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं' योजना को पूरे देश के लिए प्रासंगिक बताया। उन्होंने कहा कि इसीलिए उन्होंने हरियाणा में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना लांच की थी और अब राजस्थान में यह योजना लांच कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बेटी और धरती मां दोनों को बचाना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री ने पानी के महत्व की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पानी का इस्तेमाल किफायती रूप में करना आवश्यक है और एक भी बूंद पानी की बरबाद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की अधिकता और अभाव दोनों खतरनाक हैं। इसलिए कृषि के लिए मूल है- बूंद-बूंद पानी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों से कहा है कि नीति आयोग के तत्वाधान में सभी राज्य अपने-अपने यहां की कृषि योजनाएं प्रस्तुत करें।

अगले तीन वर्षों में 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रगतिशील किसानों की अगुवाई में पंजाब, ओडिशा, मेघालय, छत्तीनसगढ़, मध्यप्रदेश, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात के सरकारी अधिकारियों को कृषि कर्मण पुरस्कार दिए।

प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रियों की अगुवाई में अरूणाचल प्रदेश, नगालैंड, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक के अधिकारियों को प्रशस्ति पुरस्कार दिए।

इस अवसर पर राजस्थान के राज्पाल श्री कल्याण सिंह, राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, पंजाब के मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह उपस्थित थे। ■

मन की बात

परीक्षा उत्सव मनाएं विद्यार्थी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के जरिये एक बार फिर मन की बात कही। श्री मोदी इस बार बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा, मैं आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं इस विषय पर मां बाप चाहते हैं कि मैं वो बातें करूं जो वो चाहते हैं और इसी तरह शिक्षक और छात्र भी चाहते हैं। लेकिन मैं यहां उपदेश देने नहीं आया हूं।

प्रधानमंत्री ने 17 फरवरी को मन की बात में अपने छात्र जीवन को याद करते हुए कहा, मैं एक औसत छात्र था। मेरी लिखावट भी साफ नहीं थी। मैं कभी अव्वल नहीं आया। मैं आपको यह बताने नहीं आया हूं कि कैसे ज्यादा नंबर आयेंगे। कैसे सफलता मिलेगी। मैं यहां हल्की फुल्की बातें करने आया हूं।

प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी पूरी शक्ति प्रतिस्पर्धा में खप जाती है। स्वंय के विकास के लिए प्रतिस्पर्धा इतनी प्रेरणा नहीं देती। अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से कीजिए, कोशिश कीजिए कि बीते हुए कल से आज अच्छा हो।

श्री मोदी ने कहा, इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए। परीक्षा क्षमता प्रदर्शन के लिए नहीं, खुद की क्षमता पहचाने के लिए है जब आप यह मंत्र पकड़ लेंगे, आपके भीतर का विश्वास बढ़ता चला जाएगा। श्री मोदी ने एथलिट सर्गेई बूबका का उदाहण देते हुए कहा, हम लोग बड़े गर्व के साथ एथलिट सर्गेई बूबका का स्मरण करते हैं, जिन्होंने 35 बार खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। इससे पता चलता है प्रतिस्पर्धा हमेशा अपने आप से होती है। लोगों को लगता है कि परीक्षा अच्छी नहीं गयी तो पूरी दुनिया डूब जाएगी, दुनिया ऐसी नहीं है और इसीलिए कभी इतना तनाव मत पालिए।

इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए। परीक्षा क्षमता प्रदर्शन के लिए नहीं, खुद की क्षमता पहचाने के लिए है जब आप यह मंत्र पकड़ लेंगे, आपके भीतर का विश्वास बढ़ता चला जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, इच्छा. स्थिरता = संकल्प, संकल्प + पुरुषार्थ = सिद्धि होती है। श्री मोदी ने यहां उन विद्यार्थियों की चर्चा की जो परीक्षा के बोझ में दब जाते हैं। अगर हमारे जीवन में पहली बार परीक्षा दे रहे हो थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सलाह दी कि अगर आपकी कोई बहन है, तो उसे देखिये मां को घर के काम में मदद भी करती है और परीक्षा में अच्छे नंबर भी लाती है। कारण बाहरी नहीं होता भीतरी होता है। आत्मविश्वास बेहद जरूरी है। अंधविश्वास में हम बाहरी कारण ढुढ़ते हैं। जो जिंदगी की परीक्षा से लड़ता है उसके लिए क्लास की परीक्षा कोई मायने नहीं रखता। आपने भी बहुत सारा काम किया होगा जो आपके नजर में अच्छा होगा। कभी- कभी हम बहुत दूर का सोचते हैं।

परीक्षा के समय वर्तमान में जीना अच्छा होता है। क्या कोई बल्लेबाज यह सोचता है कि पिछली बार कितने में आउट हुआ। सीरिज जीतूंगा इन सब बातों पर विचार नहीं करता वह सिर्फ एक बॉल जो उसे खेलना है उसकी सोचता है। सफल जीवन का एक ही मंत्र है वर्तमान में जीना सीखिये। परीक्षा को चुनौती के रूप में नहीं अवसर के रूप में लीजिए।

श्री मोदी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यार्थियों के साथ साथ माता- पिता और शिक्षकों से भी सुझाव मांगे थे। प्रधानमंत्री गत वर्ष अक्टूबर से ही हर महीने रेडियो के जरिये देशवासियों से जुड़ते हैं। ■

श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला से मिले मोदी

भारत-श्रीलंका के बीच हुआ असैन्य परमाणु समझौता

संवाददाता द्वारा

अपने संबंधों को नए स्तर तक ले जाते हुए भारत और श्रीलंका ने एक असैन्य परमाणु समझौते पर दस्तखत किए और रक्षा व सुरक्षा सहयोग बझाने पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति श्री मैत्रीपाला सिरिसेना ने एक रचनात्मक व मानवीय रुख अपना कर मछुआरों से जुड़े संवेदनशील मुद्दे का समाधान तलाशने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की है।

सिरिसेना के साथ एक साझा प्रेस कांफ्रेंस में श्री मोदी ने कहा कि असैन्य परमाणु सहयोग पर दोतरफा समझौता हमारे आपसी विश्वास की एक और अभिव्यक्ति है। श्रीलंका से यह पहला इस तरह का समझौता है। इससे कृषि व स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों सहित अन्य मामलों में भी सहयोग के नए रास्ते खुलते हैं। सिरिसेना ने श्रीलंका का राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। उन्होंने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में महिंदा राजपक्षे को मात दी थी। राजपक्षे पिछले दस साल से श्रीलंका के राष्ट्रपति पद पर आसीन थे।

परमाणु समझौते के तहत ज्ञान व विशेषज्ञता के अंतरण व आदान-प्रदान, संसाधन साझा करने, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में कर्मियों के क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण जैसे सहयोग किए जाएंगे। रेडियोधर्मी कचरा प्रबंधन और परमाणु व रेडियोधर्मी आपदा राहत और पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग किया जाएगा। दोनों देशों ने तीन अन्य समझौतों पर भी दस्तखत किए जिसमें कृषि के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। एक और समझौते पर दस्तखत हुए जिसके तहत श्रीलंका नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना में हिस्सा ले सकेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वे और श्रीलंकाई नेता इस बात पर भी सहमत हुए कि रक्षा व सुरक्षा सहयोग बझाया जाए। उन्होंने कहा कि हमने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग, जिसमें मालदीव के साथ त्रिपक्षीय स्वरूप भी शामिल है, में प्रगति का भी स्वागत किया। उनका मानना है कि दोनों देशों का भाग्य एक-दूसरे से जुड़ा है और हमारी सुरक्षा व समृद्धि को बांटा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि दोतरफा संबंधों व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अच्छी चर्चा हुई। भारत इस बात से सम्मानित महसूस कर रहा है कि सिरिसेना ने पदभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। मछुआरों के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने और सिरिसेना ने इसे सर्वोच्च महत्त्व दिया। यह दोनों पक्षों के लोगों की आजीविका को प्रभावित करता है। हम इस बात पर सहमत हुए कि इस मुद्दे पर एक रचनात्मक व मानवीय रवैया अपनाया जाना चाहिए। हम दोनों पक्षों के मछुआरों के संघों को जल्द मिलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने वार्ता के नतीजों पर प्रसन्नता जताई और कहा-

दोनों देशों की दोस्ती सिर्फ एक-दूसरे के लिए अहम नहीं है बल्कि इसका महत्त्व पूरे क्षेत्र के लिए भी है। मैं वास्तव में संबंध सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की तारीफ करता हूं। दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। श्री मोदी ने श्रीलंका यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए सिरिसेना का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वे मार्च में श्रीलंका दौरे पर जाने के लिए उत्साहित हैं। आर्थिक संबंधों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सिरिसेना को बता दिया है कि भारत श्रीलंका में बड़े पैमाने पर निवेश को बझावा देने के लिए तैयार है। हम भारत और श्रीलंका के बीच वायु व समुद्र संपर्क बढ़ाने का भी इरादा रखते हैं।

श्रीलंका में आंतरिक तौर पर विस्थापित लोगों के लिए भारत के सहयोग से चल रही परियोजनाओं के संबंध में श्री मोदी ने कहा-उन्होंने इस मुद्दे पर शानदार प्रगति की है। इसमें आवासीय परियोजना भी शामिल है जिसके तहत 27 हजार से ज्यादा मकान पहले ही बनाए जा चुके हैं। राष्ट्रपति और मैंने प्रगति पर संतोष जताया।

मैंने राष्ट्रपति सिरिसेना को आश्वस्त किया कि भारत श्रीलंका के साथ अपनी विकास साझेदारी को लेकर प्रतिबद्ध है। सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े समझौते की तरफ इशारा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि क्रिकेट की तरह संस्कृति भी दोनों देशों के बीच एक मजबूत बंधन है। ■

किसान रैली (बारामती) गरीबी उन्मूलन में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका

सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और नरेगा के जरिए जल भंडारण क्षमताएं बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र, विद्या प्रतिष्ठान का दौरा किया और अप्पा साहेब पवार आडिटोरियम का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में गरीबी दूर करने में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। महाराष्ट्र में बारामती में किसान रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए सरकार जल भंडारण क्षमताएं बढ़ाने के उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि नरेगा के माध्यम से भी जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने अद्यतन उपलब्ध प्रौद्योगिकी के जरिए खेती को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि फरवरी से जुलाई की अवधि में स्कूल प्रयोगशालाओं में अधिक कार्य नहीं होता है अत: इस दौरान दसवीं और उससे ऊपर के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर मृदा परीक्षण कार्य में लगाया जा सकता है और ये प्रयोगशालाएं मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में काम कर सकती हैं।

प्रधानमंत्री ने भारत में खेती के विकास में योगदान के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार की सराहना की जो मंच पर मौजूद थे।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस तथा केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र, विद्या प्रतिष्ठान का दौरा किया और अप्पा साहेब पवार आडिटोरियम का उद्घाटन किया। ■

ईसाई धर्म गुरु सम्मेलन

'धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं'

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सबके लिए धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी, ताकि हर किसी के पास किसी तरह की जोर जबरदस्ती के बिना अपने धर्म का पालन करने का अधिकार हो। श्री मोदी ने 17 फरवरी को नई दिल्ली में ईसाई धर्मगुरुओं के सम्मेलन में कहा, 'मेरी सरकार पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी। हर किसी के पास किसी तरह की जोर जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के बिना किसी भी धर्म को अपनाने या पालन करने का अधिकार हो।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'मेरी सरकार सभी धर्मों का समान आदर करती है।'

श्री मोदी ने आगे कहा, 'सरकार किसी भी धार्मिक समूह को चाहे वह बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक, यह अनुमति नहीं देगी कि खुलकर या छिपकर दूसरे धर्म के प्रति घृणा फैलाए।'

संत छावरा तथा मदर यूफ्रेसिया को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जा रहे समारोह के दौरान श्री मोदी ने कहा, 'उनकी सरकार सार्वभौम घोषणा के हर शब्द और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खड़ी है।'

श्री मोदी ने कहा, भारत बुद्ध और गांधी का देश है। सभी धर्मों के प्रति समान आदर हर भारतीय के डीएनए में है। किसी भी बहाने से हम किसी भी धर्म के खिलाफ हिंसा स्वीकार नहीं करेंगे और मैं इस तरह की हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं।

उन्होंने सभी धार्मिक समूहों से इस प्राचीन देश में संयम, आपसी सम्मान तथा सहिष्णुता बरतने की अपील की और कहा कि यह हमारे संविधान में निहित है और हेग घोषणा से मेल खाता है।

कैथोलिक आर्कडायोसिस गिरजाघर के फादर सवारिमुथु संकर ने आईएएनएस से कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि अंततरू उन्होंने मुंह खोला है। हालांकि अब देर हो चुकी है, क्योंकि हम चाहते थे कि वह ईसाइयों के सामने पिछले साल ही बोलें। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी बातों पर अमल होगा।

श्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए समारोह में मौजूद नेताओं सहित सबसे समर्थन मांगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सांप्रदायिक आधार पर किसी भी तरह के बंटवारे से हम कमजोर होंगे।

ईश्वर व साथियों की सेवा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देने वाले दो संतों की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने सैंट छावरा तथा सैंट यूफ्रेसिया को मानवता के लिए प्रेरणा करार दिया। ■

प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि (11 फरवरी) पर स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करता हूं। उनके अंत्योदय और एकात्म मानववाद के आदर्श हमारा सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे।'' ■

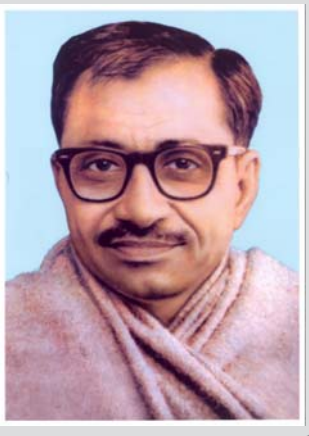

झारखण्ड

हजारीबाग रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 फरवरी को झारखंड में 79.7 किलोमीटर लंबी कोडरमा- हजारीबाग नयी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की।

हजारीबाग-कोडरमा के बीच डेमू सेवा का श्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने हजारीबाग रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित एक विशाल

सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंजन की आवाज सुनने के लिए 16 साल से यहां के लोगों के कान तरस रहे थे और आखिरकार उनकी यह प्यास भी आज बुझ गयी।

उन्होंने कहा ईमानदारी से जनहित का काम कर रहा हूं और इसके लिए जी भरकर जूझुंगा। उच्चतम न्यायालय ने कुछ महीने पहले कहा था कि कोयले की खदान के आवंटन में ईमानदारी नजर नहीं आती है और इसलिए सुप्रीमकोर्ट ने 204 कोयला खदानों का आवंटन रद्द कर दिया था। इन 204 कोयला खदानों में 40 कोयला खदान झारखंड में हैं।

श्री मोदी ने कहा कि जिन्होंने पाप किया झारखंड की संपत्ति को लूटा भारत की संपत्ति को लूटा सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर आंखे लाल की उन्हें शर्म नहीं आती है। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार ने अपनी गलती नही मानी पाप को स्वीकार नहीं किया। कोयले से जो पैसा आता था वह कहां जाता था। उसे कौन खाता था। लोकसभा में कोयले की चोरी पर जब वह बोलते थे तो विरोधी नाराज हो जाते थे।

कैग ने कहा कि कोयले की खदानें मनमर्जी से दे दी गयी जिससे राजस्व में एक लाख 86 हजार करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। संसद में कुछ समय पहले तक कैग की रिपोर्ट का मजाक उड़ाया जाता था।

श्री मोदी ने कहा कि कोयले की नीलामी की प्रक्रिया चार माह में पूरी कर दी गयी 1 फरवरी में नीलामी शुरू हुयी है। झारखंड में 40 कोयला खदानों की नीलामी करनी है जिसमें से दो की पिछले सप्ताह नीलामी हुयी 1 देश के 204 कोयला खदानों में से 15 खदानों की पिछले सप्ताह नीलामी हुयी।

उन्होंने कहा कि टीवी पर यह खबर नहीं आयी पर अखबार के कोने में यह खबर छपी। अच्छा काम टीवी पर नहीं दिख रहा है।

पन्द्रह कोयला खदानों की नीलामी से 75 हजार करोड़ रूपये मिले हैं 1 टीवी वाले इसे दिखाए या न दिखाए उनकी मर्जी अखबार वाले छापें या न छापे, उनकी मर्जी,उन्होंने कहा कि झारखंड की इन दो कोयला खदानों की नीलामी से साढ़े 12 हजार करोड़ रूपए मिले है। कैग ने जो कहा है उससे कई गुना झारखंड को मिल जाएगा।

श्री मोदी ने कहा कि अब तो लोग कह रहे हैं कि कोयले की नीलामी से सरकार को पांच लाख करोड़ सात लाख करोड दस लाख करोड़ 15 लाख करोड़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 204 कोयला खदानों की जब नीलामी होगी तो पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपये मिलेंगे लेकिन इतना पता है कि कैग ने जो कहा था उससे कई गुना अधिक मिलेगा।

उन्होंने कहा, मैं इस देश को लूटने नहीं दूंगा क्योंकि इस देश पर गरीबों का अधिकार है और सरकारी खजाना गरीबों के काम के लिए है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि गरीबों के घर में शिक्षा की रोशनी

पहुंचानी है उन्हें ताकत देनी पड़ेगी 1 शक्तिशाली बनाना होगा।

कोई गरीब नहीं रहना चाहता है। न ही अपनी विरासत के रूप में गरीबी देना चाहता है। गरीबों को अवसर की तलाश रहती है।उन्हें अवसर देना चाहिए जिससे देश नई ऊंचाई पर पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि रेल से गांव के लोगों का नाता ज्यादा रहता है वहां के लोगों के लिए रेल पटरी और रेलवे स्टेशन घूमने फिरने की जगह होती है, पहले की सरकार ने रेलवे की ताकत को नहीं पहचाना। भारतीय अर्थव्यवस्था को ताकत देने वाला क्षेत्र रेलवे है और राष्ट्र के आर्थिक विकास में यह गति देने वाला है।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का निर्माण किया था और अब मुख्यमंत्री रघुबर दास आन बान शान से इस प्रदेश को आगे ले जाएंगे।

उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत की सरकार बनायी है और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वह झारखंड आकर यहां की जनता को धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन खराब मौसम के कारण वह मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने नहीं आ पाए।

उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए वह जनता को धन्यवाद देते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा राजनीतिक दलों और राजनेताओं का चरित्र वादा भूलने वाला रहा है। लेकिन वह वादा याद कराने आए हैं। जनता के सामने मैंने वादा किया था कि आपने जो प्यार दिया उसे ब्याज समेत लौटाऊंगा और इसके लिए आज यहां मौजूद हूं। ■

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी ने भाजपाध्यक्ष से की मुलाकात

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक शीर्ष अधिकारी ने 15 फरवरी को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में मुलाकात की और दोनों पार्टियों के बीच वार्ता को बढ़ाने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया। श्री शाह से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अंतरराष्ट्रीय विभाग के मंत्री वांग जियारूई ने भाजपा मुख्यालय में मुलाकात की। बैठक के दौरान श्री शाह ने पहला आधिकारिक आगंतुक होने के लिए जियारूई की सराहना की। जियारूई की यह यात्रा बीजिंग द्वारा 'भारत भ्रमण' वर्ष मनाए जाने के तहत हो रही है।

जियारूई ने शाह को चीन आने का न्योता दिया। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच जनता के स्तर पर संवाद बढ़ाने के उपायों को प्रोत्साहन देने पर भी चर्चा की। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) राम लाल, राष्ट्रीय महासचिव श्री राम माधव और श्री भूपेंद्र यादव और पार्टी के विदेश मामलों के प्रभारी श्री विजय चौथाईवाले भी बैठक के दौरान उपस्थित थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोशियारी के नेतृत्व में भाजपा सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल में स्टडी टूर पर चीन का दौरा किया था और सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। ■

कोयला ब्लॉकों की नीलामी

'सुशासन और विकास के लिए उठाए कदमों का सुपरिणाम आने लगा है'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार द्वारा सुशासन और विकास के लिए उठाए कदमों का सुपरिणाम सामने आने लगा है। इसका ताजा उदाहरण कोयला ब्लॉकों की नीलामी है। राजग सरकार ने देशहित में कोयला ब्लॉकों की नीलामी का फैसला किया। सरकार ने 14 फरवरी को कोयला ब्लॉकों की नीलामी का पहला चरण शुरु किया। अब तक 15 कोयला ब्लॉक की नीलामी हुई है जिससे देश को भारी भरकम 1,33,513 करोड़ रुपये का लाभ होगा जिसमें 83,662 करोड़ रुपये राजस्व, 12,801 करोड़ रुपये रॉयल्टी और 37,050 करोड़ रुपये की बिजली बिल में कटौती शामिल है। अभी कई दर्जन कोयला ब्लॉकों की नीलामी होनी है और एक अनुमान के मुताबिक देश को कोयला ब्लॉक की नीलामी से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक धनराशि प्राप्त हो सकती है।

खास बात यह है कि कोयला ब्लॉकों की नीलामी का सर्वाधिक फायदा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीवसगढ़ को हुआ है जो प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से धनी लेकिन आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े राज्य हैं। अब तक जितने कोयला ब्लॉक की नीलामी हुई है उससे उड़ीसा को लगभग 607 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 39,900 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 13,210 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 1,819 करोड़ रुपये, झारखंड को 14,498 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 26,425 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

इस तरह कोयला ब्लॉकों की नीलामी के कई फायदे देश और समाज को होंगे। इससे एक ओर जहां गरीब राज्यों के सरकारी खजाने को भारी भरकम धनराशि

श्रीकांत शर्मा
राष्ट्रीय सचिव, भाजपा

मिलेगी वहीं सस्ती बिजली मिलने का रास्ता भी साफ होगा।

यह सब सुशासन और पारदर्शिता का ही परिणाम है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजग सरकार मूलमंत्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान और उसके बाद जोर देकर कहा है, ''यह गरीबों का पैसा है, सरकार इसे लुटने नहीं देगी। सरकार देश नहीं लुटने देगी।'' राजग सरकार इसी मंत्र का अनुसरण करते हुए गरीबों, आदिवासियों और किसानों के हित में कदम उठा रही है।

कोयला ब्लॉक नीलामी के अब तक के परिणामों से भाजपा का यह कथन सत्य साबित होता है कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने कांग्रेस नेताओं और उनसे संबद्ध व्यावसाइयों को मनमाने ढंग से कोयला ब्लॉक आवंटित कर देश के खजाने को कई लाख करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे पहले संसद और उसके बाहर कोयला घोटाले का मुद्दा उठाया था। भाजपा के इस आरोप की पुष्टि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में 1,86,000 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले के खुलासे के रूप में भी की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2014 को अपने ऐतिहासिक निर्णय में 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द कर पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार को देश के सामने रखा।

इस तरह कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2004 से 2011 के बीच कोयला ब्लॉकों का मनमाने ढंग से आवंटन करके न सिर्फ करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया बल्कि उसने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों को इन अमूल्य संसाधनों के लाभ से वंचित रखकर गरीबी का दंश झेलने को मजबूर किया। इतना ही नहीं कांग्रेस के नेताओं ने अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए देश को गुमराह किया और संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ उछाली।

कैग की रिपोर्ट में कोयला घोटाले का खुलासा होने पर तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था, ''जब कोयला निकाला नहीं गया है तो नुकसान कहां हुआ?'' इसी तरह यूपीए सरकार में कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने भी ''जीरो लॉस थ्योरी'' देकर देश को गुमराह किया।

अब कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया से सब कुछ स्पष्ट हो गया है। कोयला घोटाले के दोषियों को तो अदालत सजा देगी लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के गरीबों और आदिवासियों से भी माफी मांगनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस की नीतियों के चलते ही ये राज्य गरीबी का अभिशाप झेल रहे हैं। ■

भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों में राजस्थान नंबर वन

नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित तीन दिवसीय अक्षय ऊर्जा वैश्विक निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी में राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुरस्कृत किया गया।

राजस्थान के ऊर्जा राज्यमंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। पुरस्कार सम्मान में एक प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह शामिल है। इस सम्मेलन में केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्री पीयूष गोयल, केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और देश-विदेश से भारी संख्या में आये प्रतिनिधिगण मौजूद थे।

राजस्थान बनेगा सबसे बड़ा ऊर्जा हब

पुरस्कार ग्रहण करने के बाद ऊर्जा राज्यमंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति कर रहा है और वर्तमान में राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 4000 मेगावाट बिजली क्षमता अर्जित है, जिसमें 865 मेगावाट सौर ऊर्जा, 3100 मेगावाट पवन ऊर्जा और 114 मेगावाट बायो ऊर्जा शामिल है।

तीन महीने में विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किए 14 हजार मेगावाट के एमओयू

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नई 'सोलर-पॉलिसी' जारी करने के बाद प्रदेश में सोलर पार्कस की स्थापना के लिए अबतक 26 हजार मेगावाट के एमओयू हो चुके है। इसी प्रकार पिछले तीन महीने में विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी 14 हजार मेगावाट के एमओयू हुए हैं। राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए रिलायंस, सन एडीशन, अडानी, आईईएफएस जैसी अग्रणी कंपनियां आगे आ रही है।

ऊर्जा राज्यमंत्री और सचिव ने दिया प्रजेंटेशन

सम्मेलन में राजस्थान के उर्जा राज्यमंत्री श्री पुष्पेंन्द्र सिंह ने निवेशकों के समक्ष पावर पाइंट प्रजेंटेशन दिया।

इस दौरान दिखाई गई लघु फिल्म में देश-विदेश के निवेशकों को अक्षय उर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए अपने संदेश में वसुंधरा राजे ने कहा कि विशेष रूप से सौर उर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए राजस्थान सबसे उपयुक्त एवं आदर्श स्थान है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने अपनी नई सोलर एनर्जी पॉलिसी में निवेशकों के लिए कई रियायतों को शामिल किया है।

मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश में सोलर उर्जा के विकास के लिए रखे गए एक लाख मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में राजस्थान की ओर से 25 हजार हजार मेगावाट सौर उर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय कर दिया है। वसुंधरा राजे ने विश्वास व्यक्त किया कि राजस्थान निकट भविष्य में देश का सबसे बड़ा सोलर उर्जा उत्पादन प्रदेश बन कर उभरेगा।

सम्मेलन के दूसरे दिन शाम 4 बजे देश - विदेशी निवेशकों के समक्ष ऊर्जा मंत्री पुष्पेंन्द्र सिंह ने अपने प्रजेंटेशन में कहा कि राजस्थान में सौर उर्जा में एक लाख 42 हजार मेगावाट, पवन उर्जा में 5050 मेगावाट और बॉयोमास में 1039 मेगावाट उर्जा उत्पादन की क्षमता मौजूद है। वर्तमान में राज्य के विद्युत उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का योगदान 23 प्रतिशत है जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। ■

असम

स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की भारी जीत

हमारे संवाददाता द्वारा

लोक सभा चुनावों के बाद भाजपा को पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य में स्थानीय निकाय के चुनावों में ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है। 74 म्युनिसिपल बोर्डो और टाउन समितियों के चुनाव हुए, जिसमें से भाजपा ने 38 में बहुमत प्राप्त किया है। निर्वाचकों ने सत्ताधारी कांग्रेस को गहरा झटका दिया, जिसने केवल 17 निकायों में विजय प्राप्त की है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि पिछली बार सत्ताधारी पार्टी को इनमें से 71 निकायों में जीत प्राप्त हुई थी।

भाजपा की विजय अत्यधिक उत्साहवर्धक है क्योंकि भाजपा ने सिद्ध कर दिया है कि वह स्थानीय स्तर पर सत्ता करने के लिए यहां के लोगों की उच्चतम स्तर पर विकल्प बन गई है। पार्टी ने 746 म्युनिसिपल बोर्डो और टाउन समिति वार्डो में से 340 में विजय प्राप्त की है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय निकाय चुनाव 2016 की राज्य विधान सभाओं का सेमीफाइनल है।

भाजपा को सिल्चर म्युनिसिपिलिटी चुनावों में 16 सीटें हथियाकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है तो उधर कांग्रेस को केवल आठ सीटें ही प्राप्त हो सकी हैं। इससे सिल्चर में कांग्रेस की सत्ता समाप्त हो गई है। भाजपा ने थोड़े से मार्जिन से धेमाजी म्युनिसिपिलिटी भी जीती है। निचले असम क्षेत्रों में भाजपा ढुबरी म्युनिसिपल बोर्ड में भारी बहुमत प्राप्त कर सत्ता में आई है, जिसमें उसने 16 वार्डो में 10 पर विजय प्राप्त की है। मध्य और उपरी असम में भाजपा ने अनकों म्युनिसिपल बोर्डो और टाउन समितियों में विजय प्राप्त की है।

पार्टी को सोनितपुर जिला में दो म्युनिसिपल बोर्डो तथा तीन टाउन समितियों में बहुमत प्राप्त हुआ है। इसने डिब्रूगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड में भारी बहुमत प्राप्त किया है, जिसमें उसे 22 वार्डो में से 16 में जीत हासिल हुई है। कांग्रेस को मात्र 5 वार्डो में विजय मिल पाई है।

भाजपा ने नजीरा म्युनिसिपल बोर्ड में भी बहुमत प्राप्त हुआ है। मजे की बात यह है कि शिवसागर व सोनारी म्युनिसिपल बोर्डो में कांग्रेस व भाजपा को एक समान वोट प्राप्त हुए और यही स्थिति डेमाऊ तथा सिमलगुड़ी टाउन समितियों में भी रही।

कांग्रेस लगभग 15 वर्षो से राज्य में सत्ताा में है और भाजपा की विजय से स्पष्ट संकेत मिलता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। यह बात 2014 के लोकसभा चुनावों से भी मेल खाती है जहां भाजपा ने राज्य में 14 में से 7 सीटें जीतीं जबकि कांग्रेस को 2009 में मिली 7 सीटों में से केवल 3 सीटों पर ही सिमट जाना पड़ा।

गत 9 फरवरी को हुए चुनावों में अनुमानत: 14 लाख वोटरों में से 73 प्रतिशत ने अपना मत डालकर 2900 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया। प्रत्याशियों द्वारा मतपत्रों में की गई धांधली की खबर मिलने के बाद होजाई म्युनिसिपिलिटी के वार्ड सं. 2 के बूथों पर दोबारा चुनाव कराए गए। गुहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के बाद डेमाउ टाउन समिति के अंतर्गत तीन वार्डो में चुनाव स्थगित कर दिए थे।

कांग्रेस ने 2009 में नगर निकाय में बहुमत प्राप्त किया था और उसने 400 से अधिक सीटें जीत कर एजीपी और बीजेपी को क्रमश: दूसरे और तीसरे नम्बर पर ला दिया था। इस बार बांग्लादेशी आप्रवासी, बेरोजगारी और खराब आर्थिक पिछड़ापन जैसे मुद्दे थे, जिनसे लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। जबकि भाजपा के एजेंडे में विकास और समृद्धि ने राज्य में वोट प्राप्त हुए। भाजपा कांग्रेस को अगले वर्ष के चुनावों में सत्ताा से बाहर करने के लिए तैयारी कर रही है। ■

भाजपा ने स्थानीय चुनावों में महत्वपूर्ण विजय दिलाने पर मतदाताओं को धन्यवाद दिया

भाजपा ने नगर निकाय चुनावों में प्रमुख विजय दिलाने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। भाजपा ने कहा है कि असम में 9 फरवरी को 74 नगर निकायों में चुनाव हुए और असम में भाजपा के लिए स्थानीय चुनावों में क्लीन स्वीप से संकेत मिलता है कि असम में लोगों ने तय कर लिया है कि वे 2016 में होने वाले विधान सभा चुनावों में भाजपा को निर्वाचित करेंगे।

अनूठी पहल

‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ के अंतर्गत गांव अपनाने का नूतन ढंग

जैसे ही जरबा पंचायत को विजेता बनाने की घोषणा हुई, उसी पल हजारीबाग (झारखंड) के टाउन हाल में एकत्र भीड़ ने जबरदस्त हर्ष मनाया। यह समय आदर्श ग्राम प्रतियोगिता का था जो एक नूतन पारस्परिक पंचायत प्रतियोगिता का अवसर था, जिसे हजारीबाग लोक सभा और वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा द्वारा संचालित किया गया। 30 दिसंबर 2014 को आयोजित प्रतियोगिता के भाग के रूप में हजारीबाग के सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने एक प्रेस कांफ्रेस में हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र की सभी पंचायतों को इसमें भाग लेने के लिए बुलाया था। गांव के पूर्ण विकास पर ध्यान देने के लिए आदर्श ग्राम फार्म को आदर्श ग्राम प्रतियोगिता पुस्तिका के साथ सभी पंचायत मुखियाओं को वितरित किया गया था।

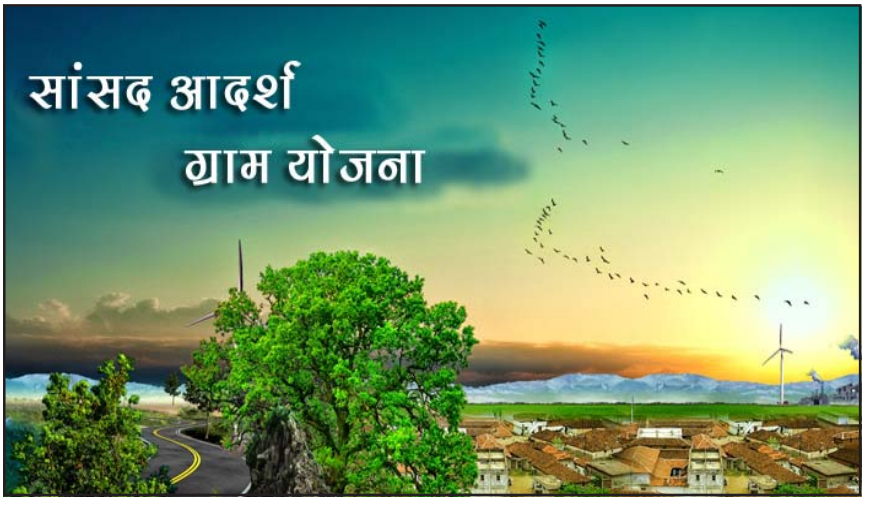

इस पुस्तिका में प्रत्येक ब्लॉक से सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन देने वाली पंचायत की घोषणा द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रत्येक ब्लॉक के विजेता को अपनी मनमर्जी की 5 केंद्रीय प्रायोजित योजना का लाभ मिलता है। सर्वश्रेष्ठ तीन विजेताओं को अपनी मर्जी की 10 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का लाभ मिलता है। वास्तव में आदर्श ग्राम योजना तथा इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैला कर प्रत्येक पंजीकृत पंचायत ग्राम समाज के सभी अंगों के प्रतिनिधियों से एक टीम गठित करती है। इस प्रकार से गठित टीम विभिन्न स्तर की ग्राम समितियों से गांव के पूर्ण विकास हेतु सलाह प्राप्त किया। एक बार जब आदर्श ग्राम फार्म पूर्णतया भर दिया गया, तब पंचायत मुखिया इसे सेवा केंद्र को 20 जनवरी से पहले सौंप दिया गया। सभी पंचायत फार्मों का 3 लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया और तीनों स्कोरों के औसत को पंचायत स्कोर माना गया। प्रत्येक ब्लॉक के सबसे अधिक स्कोर प्राप्त करने वाली पंचायत को ब्लॉक विजेता घोषित किया गया।

प्रस्तुतीकरण के आधार पर 3 विजेताओं को चुना गया। इनमें से सर्वश्रेष्ठ विजेता को आदर्श ग्राम योजना के लिए तत्काल चुना गया और दूसरे और तीसरे विजेता को बाद में गोद लिया गया। हजारीबाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 22 ब्लॉक हैं जिनमें से दो ब्लॉक हजारीबाग और रामगढ़ शहरी हैं। 20 ब्लॉकों के 117 पंचायत इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकृत कराए जिसमें से 101 ने आदर्श ग्राम फार्म प्रस्तुत किए। 101 में 20 को ब्लॉक विजेता चुना गया।

प्रतियोगिता के दूसरे चरण में 20 में से 3 को विजेता चुना गया। 3 विजेताओं में प्रथम स्थान परचुरचू ब्लॉक की जरबा पंचायत, दूसरे स्थान पर केरेडारी ब्लॉक की पेतो पंचायत और तीसरे स्थान पर चित्तरपुर ब्लॉक की साग्रीगाडा पंचायत रही। सभी तीनों पंयायतों को 10 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का लाभ मिला। जरबा को तत्काल आदर्श ग्राम के लिए गोद लिया गया जबकि साग्रीगाडा को 2016 में गोद लिया जाएगा। ■